



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]
No. 155]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2005/ज्येष्ठ 16, 1927
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2005/JYAISTHA 16, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 जून, 2005
मध्यावधि समीक्षा
अंतिम जांच परिणाम

विषय : जर्मनी तथा कोरिया जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित (एक्रीलोनिट्राइल बुटाडीन रबड़) एनबीआर के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा।

सं. 15/2/2004-डीजीएडी.—जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद नियमावली कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, कोरिया जन.गण. तथा जर्मनी से भारत में एनबीआर के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की अंतिम समीक्षा दिनांक 1 अक्टूबर, 2001 की जांच-प्रारंभ अधिसूचना द्वारा की थी जो भारत में घरेलू उत्पादक मै0 अपार इण्डस्ट्रीज लि0, मुंबई द्वारा दायर आवेदन-पत्र के आधार पर की गई थी और जबकि प्राधिकारी ने दिनांक 21 सितंबर, 2002 की अधिसूचना सं0 50/1/2001 द्वारा निष्कर्ष दिया था कि कोरिया जन.गण. तथा जर्मनी के एनबीआर पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होगी और, सिफारिश की थी कि संबद्ध माल के आयातों पर लगाया गया निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जाए। इस संबद्ध माल पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 111/2002-सीमाशुल्क द्वारा इस अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की और अवधि के लिए लगाया गया था। किंतु, उक्त अंतिम समीक्षा में इस शुल्क के स्वरूप को मूल जांच में लगाए गए निर्धारित शुल्क से बदलकर संदर्भ कीमत आधार बना दिया गया था। निर्यातक ने अन्य मुद्दों में सीएसटीएटी में लैंडेड मूल्य आधार पर निर्धारित से संदर्भ कीमत में इस परिवर्तन को चुनौती दी। (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण)

सेस्टेट ने अपने दिनांक 1/7/2004 के आदेश सं० 14-18/04-एडी द्वारा शुल्क का स्वरूप को संदर्भ कीमत से संशोधित कर निर्धारित शुल्क कर दिया और इस शुल्क की राशि को कोरियाई अपील करने वाली कंपनी मै० कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन पर 106.16 अम.डा. प्रति मी.टन की दर से निर्धारित कर दिया ।

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी को संबद्ध माल के कोरियाई निर्यातक अर्थात् मै० कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन की ओर से कोरिया जन.गण. के संबद्ध माल के एक भारतीय आयातक अर्थात् मै० ऋषिरूप पोलीमर्स लि० से बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर संबद्ध माल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा किए जाने हेतु एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। उपर्युक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक जानकारी के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचार किया कि निर्यातक द्वारा प्राधिकारी के संज्ञान में लाई गई बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना यथोचित रहेगा । प्राधिकारी ने पाटनरोधी संबंधीकरण के अनुच्छेद 11.2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9क(5) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के तहत, उपर्युक्त संबद्ध देशों के विरुद्ध लगे शुल्क के संबंध में पाटनरोधी मध्यावधि समीक्षा जांच आरंभ करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29.03.2004 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि इस बात का निर्धारण कर दिया जाए कि क्या इस शुल्क का भार पाटन को समाप्त करने हेतु अपेक्षित है और क्या इस शुल्क को समाप्त किए जाने अथवा उसमें कमी-बेशी करने अथवा दोनों के परिणामस्वरूप क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी ।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:-
 - i) यह समीक्षा आरंभ किए जाने के पश्चात् प्राधिकारी ने संगत जानकारी मंगाने के प्रयोजनार्थ नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देशों के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों और भारत के घरेलू उद्योग को जांच आरंभ अधिसूचना के साथ-साथ प्रश्नावलियां भेजीं ।
 - ii) नियम 6(2) के अनुसार, जांच आरंभ किए जाने के बारे में संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों/उच्चायोगों/आयुक्तियों को सूचित किया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावली का प्रत्युत्तर देने हेतु अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें ।
 - iii) नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक जानकारी मंगाते हुए भारत में संबद्ध माल के ज्ञात आयातकों तथा उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं ।

- iv) जांच दिनांक 01-01-2003 से 31.12.2003 तक की अवधि के लिए की गई। किंतु, क्षति संबंधी जांच वर्ष 2000-01 से 2002-03 और जांच-अवधि के लिए की गई।
- v) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस) से अनुरोध किया गया कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच-अवधि के लिए संबद्ध माल के आयात के ब्यौरे प्रदान करें।
- vi) इस समीक्षा के लिए इस आवेदक को छोड़कर, कोरिया जन.गण. के किसी अन्य निर्यातक से जांच-आरंभ अधिसूचना का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
- vii) किसी भी नामोद्दिष्ट देश के किसी अन्य निर्यातक ने जांच-आरंभ अधिसूचना का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। मै0 लैंगसेस एजी, (बायर) जर्मनी ने अपने संक्षिप्त निवेदन में प्राधिकारी को सूचित किया कि बायर ने अन्दरूनी तौर पर निर्णय लिया है कि और अधिक संसाधनों तथा व्यय का निवेश नहीं किया जाए और अपने मामले के प्रति ऐसी दलील दी कि बायर द्वारा उसकी कई बार समीक्षा की गई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
- viii) मै0 अपार इण्डस्ट्रीज लि0, मुंबई जो संबद्ध माल के घरेलू उत्पादक और मूल जांच में मूल याचिकाकर्ता भी हैं, ने समीक्षा का विरोध करते हुए अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए।
- ix) नीचे बताए गए अन्य इच्छुक पक्षकारों ने जांच के विभिन्न चरणों पर जांच-आरंभ अधिसूचना का अपना-अपना प्रत्युत्तर दर्ज कराया:-
 - क) आल इंडिया फैडरेशन ऑफ रबड़ फुटवियर मैन्यूफैक्चरर्स
 - ख) आल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
- x) प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा व्यक्त सभी विचारों तथा निवेदनों पर मौजूदा जांच के संगत सीमा तक विचार किया है।
- xi) प्राधिकारी ने जांच के दौरान विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा किए गए निवेदनों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाइल के रूप में इच्छुक पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुला रखा।

- xii) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी की यथासंभव सीमा तक पड़ताल की जिससे हुई क्षति की जांच की जा सके और अनुकूल उत्पादन-लागत तथा संबद्ध माल की उत्पादन एवं बिक्री-लागत की सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर गणना की जा सके जिससे यह पता लग जाए कि क्या पाटन मार्जिन से कम राशि का पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त रहेगा ।
- xiii) प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार, सामान्य मूल्य एवं पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ इस विषय-समीक्षा के लिए सहयोगकर्ता निर्यातक तथा आवेदक के आंकड़ों की भी पड़ताल की और निर्यातक के परिसरों में की गई पड़ताल के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की । यह सत्यापन रिपोर्ट आवेदक निर्यातक को उपलब्ध कराई गई और उनसे इस पर टिप्पणियां मांगी गई । किंतु निर्यातक ने इस सत्यापन रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दर्ज नहीं कराई ।
- xiv) प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षकारों की सुनवाई करने हेतु दिनांक 15.7.2004 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जिसमें घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों के संबद्ध माल के निर्यातकों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे । सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने-अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त लिखित निवेदनों पर इस जांच में विचार किया गया है ।
- xv) प्राधिकारी ने मामले के उन आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया जिनके आधार पर सभी इच्छुक पक्षकारों को दिनांक 15 मार्च, 2005 के अलग से प्रकटन विवरण-पत्रों के जरिए निर्णय दिए गए । इन इच्छुक पक्षकारों से कहा गया कि वे अपनी-अपनी टिप्पणी दिनांक 23 मार्च, 2005 तक दर्ज करा दें । कोरिया के आवेदक निर्यातक ने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया और अंतिम जांच परिणाम जारी किए जाने से पहले प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु अनुरोध किया । इस निर्यातक को अतिरिक्त समय और प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई के दो अवसर प्रदान किए गए । किंतु इस निर्यातक ने दिए गए सुनवाई हेतु अवसर का लाभ नहीं उठाया ।
- xvi) आवेदक निर्यातक सहित इच्छुक पक्षकारों द्वारा दर्ज प्रकटन विवरण-पत्र संबंधी टिप्पणियों, जहां तक वह वैध एवं संगत हैं, पर इन जांच-परिणामों में विचार किया गया है ।
- xvii) अधिसूचना में **** वाला अंश इच्छुक पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अन्तर्गत उसी पर विचार किया गया है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु"

4. उक्त मूल जांच में शामिल उत्पाद ऐक्रीलोनिट्राइट बुटाडीन रबड़ (एनबीआर) रहा था जो उपर्युक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 40 के शीर्ष सं० 40025900 और आईटीसी एचएस वर्गीकरण के अन्तर्गत आता है। विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के मुद्दे पर किसी भी इच्छुक पक्षकार द्वारा कोई भी तर्क नहीं दिया गया है। इसमें आवेदक निर्यातक का यह तर्क शामिल नहीं है कि मूल जांच के प्रारंभ तथा उसमें शामिल उत्पाद पर उन्होंने विवाद किया और यह मामला अभी भी न्यायाधीन है। अतः प्राधिकारी मूल जांच के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की पुष्टि करता है। किंतु, यह वर्गीकरण मात्र संकेतात्मक था और उसकी मौजूदा जांच के दायरे पर किसी भी तरह से कोई बाध्यता नहीं है।

घ. समीक्षा का आरंभ तथा दिए गए तर्क

घ.1 समीक्षा के संबंध में आवेदक अथवा मै० कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन (केकेपीसी) और मै० ऋषिरूप पोलीमर्स लि० के विचार

5. समीक्षा हेतु मै० ऋषिरूप पोलीमर्स लि० द्वारा आवेदन-पत्र अपनी ओर से और मै० कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लि० (केकेपीसी), कोरिया जन.गण. की ओर से दायर किया गया है।
6. आवेदकों ने समीक्षा हेतु अनुरोध करते हुए अपने मूल आवेदन-पत्र में निम्नलिखित निवेदन किए थे:
- कि बाजार दशाओं में काफी बदलाव आ गए हैं जिससे पाटनरोधी उपायों की समीक्षा करना अपेक्षित है;
 - कि आयात कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है और घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हो गया है;
 - कि एनबीआर पर लगे सीमाशुल्क में पिछली समीक्षा जांच में जांच-अवधि से काफी गिरावट आई है जो 38.5% से घटकर 20% रह गया और इसीलिए संदर्भ कीमत तथा लैण्डेड मूल्य के बीच अन्तर के रूप में संदर्भ कीमत आधार पर अब संग्रहीत पाटनरोधी शुल्क अन्तिम समीक्षा जांच में निर्धारित वास्तविक पाटन मार्जिन से कहीं अधि है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1) का उल्लंघन है।
7. सारांश में, आवेदक ने निवेदन किया है कि लगे हुए पाटनरोधी शुल्क की बदली हुई परिस्थितियों में समीक्षा किए जाने हेतु पर्याप्त आधार हैं और आरंभ की गई समीक्षा नियमानुसार उचित है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

8. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न निवेदनों में इस समीक्षा को आरंभ किए जाने का विरोध किया है और अन्य बातों के साथ-साथ निवेदन किया है:

- कि मौजूदा समीक्षा पर्याप्त औचित्य के बिना आरंभ की गई है और यह समीक्षा हेतु आवेदक द्वारा दायर भ्रामक है निरूपण पर आधारित है।
- कि निर्यातक ने वास्तव में संबद्ध कच्चे माल की लागत में वृद्धि जोड़ते हुए पाटन को बढ़ा दिया है।
- कि पाटनरोधी शुल्क की राशि वास्तविक रूप से इतनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वह घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का उपयुक्त तरीके से निवारण हो सके।
- कि आवेदक निर्यातक समीक्षा हेतु अपने आवेदन-पत्र के पर्याप्त अगोपनीय खुलासों को प्रस्तुत करने में असफल रहा।
- कि कोरियाई निर्यातक द्वारा किए गए समीक्षा-अनुरोध के आधार पर जर्मनी को इस समीक्षा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

9. समीक्षा आरंभ किए जाने पर घरेलू उद्योग की आपत्ति के प्रत्युत्तर में इन आवेदकों ने आगे यह भी निवेदन किया है कि:

- उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह सदर्थ कीमत में संशोधन हेतु एक सीमित एवं समयोचित समीक्षा करें ताकि एकत्रित पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से अधिक नहीं हो क्योंकि सीमाशुल्क को मध्यवर्ती समयावधि के दौरान 38.5% से संशोधित कर 20% पर निर्धारित किया गया। यह स्वयं बदली हुई परिस्थितियों के रूप में पर्याप्त साक्ष्य बन गया जिससे समीक्षा की आवश्यकता हुई। यह प्राधिकारी के लिए एक दायित्व बन गया कि वह इस शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता की जांच किए जाने हेतु मध्यावधि समीक्षा करें।
- कि घरेलू उद्योग इस बात की मांग का स्वयं विरोध करता आया है कि एक देश के विरुद्ध कोई सीमित समीक्षा नहीं की जा सकती है जबकि इसी तरह के मामले से संबंधित वर्ष 1999 में उनके द्वारा दायर पिछली समीक्षा याचिका को उन्होंने वापस ले लिया था और प्राधिकारी द्वारा समीक्षा को इस आधार पर समाप्त किया गया था कि प्राधिकारी एक देश के विरुद्ध सीमित समीक्षा नहीं कर सका जब वह उपाय एक से अधिक देशों के विरुद्ध संचित हो गया था और सभी देशों के वरुद्ध जांच की साथ-साथ समीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी।

- घरेलू उद्योग के गहन पाटन के दावे के विरुद्ध आवेदक ने इस समीक्षा के पक्ष में यह तर्क दिया है कि ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को चाहिए कि वे इसका विरोध करने की बजाए वास्तव में इसका समर्थन करें।

घ.3 अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार

10. इस समीक्षा के संबंध में किसी भी अन्य इच्छुक पक्षकार ने कोई पर्याप्त निवेदन नहीं किया है।

घ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी ने यह समीक्षा जांच को आरंभ किए जाने के संबंध में इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की है।
12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित धारा 9क(5) में यह उपबंध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क-भार को जारी रखे जाने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करेगा और यदि वह उसे प्राप्त जानकारी के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे शुल्क-भार को जारी रखे जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है तो ऐसी स्थिति में वह उसे समाप्त किए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगा।
13. करार के अनुच्छेद 11.2 में यह उपबंध है कि प्राधिकारी इस शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता के संबंध में यदि आवश्यक हुआ, अपनी पहल पर समीक्षा करेंगे, बशर्ते निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए हुए एक यथज्ञोचित समयावधि समाप्त हो गई हो अथवा ऐसा वह किसी ऐसे इच्छुक पक्षकार के अनुरोध पर करें जो समीक्षा की आवश्यकता को पुष्ट करते हुए सकारात्मक जानकारी प्रदान करें। इच्छुक पक्षकारों को प्राधिकारियों से यह अनुरोध करने का अधिकार होगा कि वह इस बात की जांच करें कि क्या पाटन को समाप्त करने हेतु लगे हुए शुल्क का जारी रखा जाना आवश्यक है, क्या क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी यदि शुल्क समाप्त किया जाए अथवा उसमें कमी-बेशी की जाए अथवा दोनों ही बातें हों। यह पैराग्राफ के तहत की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप यदि प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए रखना आवश्यक नहीं है तो तब उसे तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।
14. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 के तहत समीक्षा के आधारों को पुष्ट करना आवश्यक है और आवेदक ऐसा करने में असफल रहा है। अतः समीक्षा करना दोषपूर्ण है। आवेदक निर्यातक ने तर्क दिया है कि भारतीय कानून में प्राधिकारी सह यह अपेक्षा है

कि वह शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता के संबंध में समय-समय पर समीक्षा करें और उसमें समीक्षा चाहने वाले पक्षकार पर दायित्व नहीं थोपा गया है कि वह पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करवा ही दे। किन्तु उन्होंने अनेक आधारों पर पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 के तहत यथापेक्षानुसार सकारात्मक जानकारी उपलब्ध कराई और समीक्षा आरंभ करने हेतु प्राधिकारी के पास जानकारी मौजूद थी उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि संदर्भ कीमत आधार पर शुल्क लगाए जाने के बाद सीमाशुल्क में पर्याप्त गिरावट आना ही स्वयं समीक्षा किए जाने हेतु एक पर्याप्त आधार बन जाता है क्योंकि एकत्रित शुल्क पाटन मार्जिन से अधिक है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1) और उक्त करार के संगत अनुच्छेदों का उल्लंघन है।

15. प्राधिकारी ने इन तर्कों की जांच की है और उसका विचार है कि नियम 23 में "संतुष्टि" का आशय एक उचित जांच के पश्चात लगे हुए शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता के संबंध में प्राधिकारी की संतुष्टि से है न कि समीक्षा करने से। कोई समीक्षा करने के लिए जरूरी यह है कि प्राधिकारी के पास सकारात्मक जानकारी उपलब्ध हो जिस पर प्राधिकारी यह निर्णय लेने हेतु विश्वास कर सकता है कि क्या लगाए गए शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता की जांच करने हेतु समीक्षा करना अपेक्षित है। मौजूदा मामले में आवेदक ने अपने समीक्षा-आवेदन में प्राधिकारी के समक्ष पर्याप्त सकारात्मक जानकारी दर्ज करा दी थी और इस प्रकार दायर सकारात्मक जानकारी के आधार पर समीक्षा आरंभ की गई। विभिन्न पक्षकारों द्वारा दावों तथा प्रतिदावों की पुष्टि में साक्ष्य प्रस्तुत करना जांच का मुद्दा है और इन्हें उस पक्षकार सहित सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत करना अपेक्षित है जो जांच के दौरान समीक्षा किए जाने हेतु अनुरोध कर रहा है। किन्तु इस समीक्षा का परिणाम समीक्षा हेतु विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।
16. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि इस समीक्षा में अन्य अन्तर्ग्रस्त देश अर्थात् जर्मनी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि समीक्षा हेतु अनुरोध कोरिया गणराज्य के एकल निर्यातक से प्राप्त हुआ है। प्राधिकारी का विचार है कि उक्त करार तथा नियमावली में प्राधिकारी पर यह दायित्व सौंपा गया है कि प्राधिकारी लागू उपायों को जारी रखे जाने संबंधी आवश्यकता की समीक्षा करें। अतः उपर्युक्त करार तथा पाटनरोधी नियमावली में कोई भी प्रावधान प्राधिकारी को इस समीक्षा के दायरे में सभी देशों को शामिल करने से नहीं रोकता है जबकि प्राधिकारी के पास उपलब्ध सकारात्मक जानकारी यह दर्शाती है कि ऐसी समीक्षा करना समुचित है।
17. प्राधिकारी ने जांच के दौरान उठाए गए सभी अन्य तर्कों और इच्छुक पक्षकारों द्वारा खुलासा निवेदन-पश्चात के तर्कों की इस जांच के संगत सीमा तक जांच की है और उन्हें जांच-परिणामों में उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

ड. पाटन का निर्धारण**ड.1 कोरिया जनवादी गणराज्य**

18. कोरिया के एकमात्र निर्यात/विनिर्माता अर्थात् वर्तमान समीक्षा हेतु आवेदक, मै0 कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन ने समीक्षा आरंभ के पश्चात् प्रश्नावली में अपना प्रत्युत्तर दायर किया। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली-प्रत्युत्तर की भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पड़ताल की और पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

ड.1.1 मै0 कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन (केकेपीसी), कोरिया जन.गण.**सामान्य मूल्य:**

19. मै0 केकेपीसी ने अपने उत्सान संयंत्र द्वारा उत्पादित एनबीआर के विभिन्न ग्रेडों की घरेलू तथा निर्यात बिक्रियों के ब्यौरे के साथ-साथ विस्तृत प्रश्नावली-प्रत्युत्तर दायर किया। विचाराधीन अवधि के दौरान यह पाया गया कि इस निर्यातक ने भारत को तीन ग्रेडों अर्थात् केएनबी35 केएनबी35 एलएम और केएनबी40 एम निर्यात किया है। निर्यात ने अपने घरेलू बाजार में भी इन ग्रेडों की पर्याप्त बिक्री की थी। अतः पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ इन ग्रेडों को करार के अनुसार इसके आशय के भीतर समान वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया है।
20. विनिर्माता अर्थात् मै0 केकेपीसी की लागत-सत्यापन, उनके घरेलू-बिक्री सौदों जिनमें दावे किए गए विभिन्न समायोजन शामिल हैं, की मौके पर पड़ताल के दौरान उनके रिकार्ड से पड़ताल की गई। मौके पर पड़ताल के आधार पर सत्यापन की एक प्रति निर्यातक को भेजी गई और उनसे कहा गया कि वे पड़ताल के विभिन्न पहलुओं पर अपनी टिप्पणी तथा स्पष्टीकरण दें। अपने प्रकटन पश्चात् विवरण-पत्र में उन्होंने तर्क दिया है कि उन्हें भेजी गई सत्यापन रिपोर्ट बिना क्षेत्राधिकार और निर्धारित प्रक्रिया के बिना है और इसीलिए वह वैध नहीं है। प्राधिकारी नोट करता है कि यह सत्यापन प्राधिकारी की ओर से सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत करार के अनुबंध 1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया और निर्यातक ने इस सत्यापन में सहभागिता की। इस सत्यापन के आधार पर और निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्राधिकार के तहत विभिन्न निर्धारण तत्वों सहित सत्यापन दल के निष्कर्षों को उक्त करार के अनुच्छेद 6(9) की भावना में निर्यातक को सूचित किया गया। निर्यातक से यह भी अनुरोध किया गया कि वह विभिन्न निष्कर्षों पर अपनी टिप्पणी करे और जहां कहीं अपेक्षित हो, अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करें। निर्यातक ने टिप्पणी देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा लेकिन वह कोई टिप्पणी अथवा अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने में असफल रहा। अतः यह माना गया कि उन्हें उक्त रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा विरोध नहीं करना है।

21. जहां तक विनिर्माण लागत तथा बिक्रियों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि कंपनी ने अपनी रबड़ विनिर्माण कार्यकलापों में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास व्यय शीर्षों पर काफी खर्च किया। निर्यातक ने दावा किया है कि ये खर्चे एनबीआर व्यवसाय पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि जांच के अधीन शामिल अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया में केवल विशिष्ट उत्पाद ही कवर होते हैं। इस निर्यातक ने प्रकटन पश्चात अपने निवेदनों में भी अपना यह रुख दोहराया है। किंतु, निर्यातक ने इस संबंध में अपना उत्तर दर्ज नहीं कराया है हालांकि यह मुद्दा उन्हें सत्यापन रिपोर्ट की मार्फत सूचित किया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि निर्यातक ने अपने सदन-गत अनुसंधान एवं विकास द्वारा प्रतिक्रिया समय, खपत-मानदंडों आदि के रूप में एनबीआर उत्पादकता में काफी सुधार किए जाने का दावा किया है। अतः कंपनी का यह दावा स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया क्योंकि अनुसंधान एवं विकास में सभी उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया में काफी सुधार तथा प्रगति शामिल है। तदनुसार, सभी उत्पादों पर यथानुपात आधार पर अनुसंधान एवं विकास लागत लगाई गई है।
22. इसी प्रकार घरेलू बिक्रियों तथा निर्यात बिक्रियों के संबंध में दावा कि गए पैकिंग तथा परिवहन प्रभारों संबंधी अलग-अलग समायोजन को अनुमेय नहीं पाया गया है क्योंकि सत्यापन के समय निर्यात तथा घरेलू बिक्रियों को बीच कोई अंतर दिखाया नहीं गया था।
23. इसी प्रकार, निर्यातक ने विभिन्न उत्पादों के बीच एसजीए प्रभारों तथा फैक्टरी के ऊपरी खर्चों के आबंटन की पद्धति का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। किंतु निर्यातक ने सत्यापन रिपोर्ट पर कोई भी टिप्पणी दर्ज नहीं कराई है। अतः, सत्यापन रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों को निर्यातक द्वारा स्वीकार कर लिया माना गया है। तदनुसार, लागत के इन तत्वों पर आवश्यक समायोजन कर लिए गए हैं ताकि निर्यातक के संबंध में यथोचित उत्पादन लागत का निर्धारण किया जा सके। अतः इस निर्यातक के संबंध में संबद्ध उत्पाद की उत्पादन लागत *** अमरीकी डालर/मी.टन निर्धारित की गई है।
24. केकेपीसी ने जांच-अवधि के दौरान एनबीआर के विभिन्न ग्रेडों सहित ** 12 मी.टन की पर्याप्त घरेलू बिक्री की थी। इस प्रकार निर्धारित उत्पादन-लागत के अधर पर उनके घरेलू बिक्री सौदों पर सामान्य व्यापार परीक्षण किया गया। इस सामान्य व्यापार परीक्षण में पाई गई घरेलू बिक्री सौदों की भारित औसत को उनके सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है। निर्यातक ने निवल कारखानागत कीमत-निर्धारण हेतु घरेलू बिक्री सौदा-मूल्य में विभिन्न समायोजनों का दावा किया है। किंतु, प्राधिकारी यह पाता है कि घरेलू बिक्रियों तथा निर्यात बिक्रियों के अन्तर्देशीय परिवहन तथा पैकिंग के लिए दावा किए गए अलग-अलग समायोजन के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए। अतः इन कारकों के लिए समायोजन औसत आधार पर स्वीकार किए गए हैं। घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में व्यापार समायोजनों के विभिन्न अनुमेय स्तर लागू किए जाने के पश्चात इस निर्यातक के लिए कारखानागत सामान्य मूल्य का निर्धारण **** अम.डा./मी.टन किया गया है।

निर्यात कीमत

25. जांच-अवधि के दौरान केकेपीसी ने भारत को विभिन्न ग्रेडों के **** मी.टन एनबीआर का निर्यात किया था। भारत को किए गए निर्यात की वास्तविक सीआईएफ कीमत के आधार पर भारत के लिए निवल कारखानागत निर्यात कीमत की गणना समुद्री भाड़ा तथा बीमा, अन्तर्देशीय भाड़ा, कमीशन तथा पैकिंग के लिए सीआईएफ निर्यात कीमत का समायोजन कर की गई है। अन्तर्देशीय परिवहन तथा पैकेजिंग के अलग-अलग समायोजनों के संबंध में निर्यातक का दावा इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिए पर्याप्त औचित्य तथा साक्ष्य की कमी पायी गई। उपरोक्त के आधार पर भारित औसत निवल कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण **** अम.डा./मी.टन किया गया है।

ड.1.2 कोरिया गणराज्य के सभी अन्य निर्यातक

सामान्य मूल्य

26. इस समीक्षा प्रारंभ के प्रत्युत्तर में कोरिया जन.गण. के किसी अन्य निर्यातक ने प्राधिकारी के समक्ष कोई निवेदन नहीं किया। अतः कोरिया के सभी अन्य निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरीधी नियमावली के नियम 6.8 के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया जाए। इस निर्धारण के प्रयोजनार्थ सहकारी निर्यातों के उच्चतम घरेलू सौदा-मूल्य को सहयोगकारी निर्यातकों के आंकड़ों के आधार पर ग्राह्य समायोजनों की अनुमति के बाद प्राप्त सामान्य मूल्य के रूप में अपनाया गया है। तदनुसार, सभी अन्य निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य **** अम.डा./मी.टन पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।

निर्यात कीमत

27. निवल निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों के आधार पर कोरिया से न्यूनतम निर्यात सौदा मूल्य के आधार पर किया गया है और ऐसा परिवहन, समुद्री भाड़ा, कमीशन, आदि के समायोजनों की अनुमति दिए जाने के बाद किया गया है।

ड.2 जर्मनी

28. प्राधिकारी नोट करता है कि जर्मनी के किसी भी निर्यातक ने समीक्षा जांच आरंभ होने के प्रति कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। जैसाकि पहले नोट किया गया है, मै0 लैंगसेस एजी, (बॉयर), जर्मनी ने अपने संक्षिप्त निवेदन में प्राधिकारी को सूचित किया है कि बॉयर ने

अंदरूनी तौर पर निर्णय किया है कि वे और आगे संसाधनों तथा खर्चों का निवेश नहीं करेंगे और अपने मामले में यह तर्क दिया है क्योंकि इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की कई बार समीक्षा कर ली गई है जिसमें बॉयर को कोई सफलता नहीं मिली। अतः, कंपनी ने कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर दर्ज नहीं कराया है अथवा जांच में अपेक्षित तरीके में सहयोग नहीं किया है। जर्मनी के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच का कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने जर्मनी में संबद्ध माल के सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6.8 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। तदनुसार, जर्मनी के सभी निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य **** अम.डालर/मी.टन निर्धारित किया गया है।

29. जर्मनी की निर्यात कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा रिपोर्ट की गई भारत औसत निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है जिसमें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़े, बीमा, अन्तर्देशीय भाड़ा तथा कमीशन से संबंधित ग्राह्य समायोजनों की अनुमति दी गई है। तदनुसार, जर्मनी के सभी निर्यातकों के संबंध में निवल कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण **** अम.डालर/मी.टन किया गया है।

ड.3 पाटन मार्जिन

30. कारखानागत मूल्य पर निर्धारित भारत औसत सामान्य मूल्य की तुलना कारखानागत स्तर पर निर्धारित भारत औसत निवल निर्यात कीमतों से की गई है ताकि संबद्ध देशों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सके जोकि निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन की गणना

	सामान्य मूल्य US\$/ मी.टन	निर्यात कीमत US\$/ मी.टन	पाटन मार्जिन US\$/ मी.टन	पाटन मार्जिन%
मै0 केकेपीसी, कोरिया जन.गण.	***	***	***	13.22%
कोरिया के सभी अन्य निर्यातक	***	***	***	48.75%
जर्मनी के सभी निर्यातक	***	***	***	93.115

31. प्राधिकारी नोट करता है कि इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन पर्याप्त है और यह निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर है।

32. अपने प्रकटन पश्चात् निवेदन में आवेदक निर्यातक की ओर से मै ऋषिरूप पोलिमर ने अनेक जानकारीयां मांगी जिसमें सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के निर्धारण की पद्धतियों तथा अनुमेय समायोजन का विस्तृत रूप शामिल है। उन्होंने अंतिम जांच परिणामों को जारी होने से पहले प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु भी अनुरोध किया और इस संबंध में मुम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की। प्राधिकारी ने उन्हें उक्त सुनवाई के लिए अनेक अवसर प्रदान किए जिनका उन्होंने लाभ नहीं उठाया।
33. मै0 ऋषिरूप ने अपने निवेदन में तर्क दिया है कि नए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन जारी होने से पहले इस मामले की सुनवाई नहीं की। प्राधिकारी नोट करता है कि नियमावली में केवल इस कारण नहीं सुनवाई किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पद पर एक के बाद दूसरा उत्तराधिकारी आ जाए। यह भी नोट किया जाए कि न्यायवत अथवा न्यायिक जांच-पड़ताल में भी न्यायवत अथवा न्यायिक प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अभिन्न अंग होता है और उत्तराधिकारी व्यक्ति रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करे ताकि कोई निर्णय लिया जा सके। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) में प्रावधान है कि सार्वजनिक सुनवाई में प्राधिकारी के समक्ष इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए मौखिक निवेदन रिकॉर्ड में लिए जाने हेतु लिखित रूप में आवश्यक रूप से ज्यू का त्यू प्रस्तुत किया जाए। सुनवाई के पश्चात् पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित निवेदन जांच के रिकॉर्ड का अभिन्न रूप बन जाते हैं जिसके आधार पर प्राधिकारी अंतिम निर्णय लेता है। मौजूदा मामले में पिछले निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मौखिक सुनवाई के पश्चात् इस आवेदक सहित सभी इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित निवेदनों को प्रकटन विवरण-पत्र जारी किए जाने से पहले इस प्राधिकारी द्वारा हिसाब में लिया गया था। किंतु आवेदक के अनुरोध पर प्राधिकारी ने उन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए तीन अवसर प्रदान किए ताकि वे प्रकटन के पश्चात् भी अपने निवेदन प्रस्तुत करें, हालांकि ऐसा करना प्राधिकारी की सामान्य प्रक्रिया में नहीं आता है किंतु सुनवाई के लिए अपने अनुरोध के बावजूद आवेदक ने इन अवसरों का लाभ नहीं उठाया। अतः प्राधिकारी इस संबंध में आवेदक की दलील में कोई गुणावगुण नहीं पाता है।
34. अपने विभिन्न निवेदनों में मै0 ऋषिरूप ने जांच की शक्ति, सत्यापन रिपोर्ट जारी करने की शक्ति, समीक्षा करने संबंधी प्राधिकारी की शक्ति, आदि के संबंध में अनेक मुद्दे उठाए हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि यही मुद्दे उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाए हैं और मामला न्यायाधीन है। इस संबंध में अधिनियम के अनुसार जांच किए जाने के संबंध में प्राधिकारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि जांच सुस्थापित पद्धतियों के अनुसार की जा रही है जिसे विश्व-भर में अपनाया जाता है और उक्त करार अथवा भारतीय पाटनरोधी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने आप जांच करेगा। अतः निर्यातक के तर्क, तर्कसंगत नहीं हैं।

35. मै0 ऋषिरूप ने प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन के निर्धारण का भी विरोध किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि उनके दावे किए गए अनुसार घरेलू बिक्रियों तथा निर्यात बिक्रियों की बीच पैकिंग लागत तथा अन्तर्देशीय भाड़ा अंतर को गलती से अस्वीकार किया गया है। हालांकि पिछली जांच में उसकी अनुमति दी गई थी। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि पैकिंग तथा अन्तर्देशीय भाड़ा तथा अनुसंधान एवं विकास खर्चों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट इस निर्यात को नवम्बर, 2004 में भेजी गई। निर्यातक ने अपने दिनांक 19 नवंबर के पत्र द्वारा 30 नवंबर तक का समय इसलिए मांगा ताकि वह अपने प्रत्युत्तर दर्ज करा सके लेकिन आज तक भी उन्होंने उक्त रिपोर्ट पर कोई भी टिप्पणी दर्ज नहीं कराई है। अतः यह माना गया कि उक्त रिपोर्ट पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है और प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई करने हेतु बाध्य हुआ।
36. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि सत्यापन रिपोर्ट के जरिए उनके संज्ञान में बहुत पहले लाए गए तथ्यों पर टिप्पणी करने की बजाए, जोकि तथ्यों के प्रकटन के रूप में था, निर्यातक ने इन मुद्दों पर विरोध प्रकटन विवरण जारी हो जाने के बाद ही किया है। किंतु, प्राधिकारी ने उनकी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में की गई आपत्तियों को संज्ञान में लिया है। यह नोट किया जाता है कि पैकिंग लागत में दावे किए गए अंतर को उत्पादन तथा पैकिंग प्रक्रिया तथा प्रस्तुत आंकड़ों के वास्तविक सत्यापन के आधार पर अमान्य किया गया और तदनुसार, ऐसा उन्हें काफी पहले सूचित किया गया। आगे यह भी नोट किया जाता है कि भारत के लिए घरेलू एवं निर्यात पैकिंग के प्रकार के संबंध में प्रश्नावली प्रत्युत्तर तथा प्रकटन पश्चात निवेदन के बीच अनेक विरोधाभास सामने आए हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि अन्य देशों से इसी प्रकार के उत्पाद के संबंध में चल रही एक और जांच में निर्यातकों ने किसी भी पैकिंग अंतर का दावा नहीं किया है क्योंकि घरेलू तथा विदेशी उपभोक्ताओं के लिए पैकेजिंग आवश्यक रूप से एकसमान होता है। घरेलू बिक्रियों के लिए जहां कहीं खानों का प्रयोग किया गया है उनका दोबारा प्रयोग कम से कम 6 से 8 चक्रों के लिए किया जाता है और लागत अंतर नगण्य हो जाती है।
37. जहां तक भाड़ा अंतर के मुद्दे का संबंध है प्राधिकारी नोट करता है कि अलग-अलग बीजकों के संबंध में पड़ताल हेतु घरेलू एवं निर्यात बिक्रियों के लिए कोई भी अंतर्देशीय भाड़ा बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रस्तुत बीजकों का संयोजन किसी विशेष बिक्री बीजक से नहीं किया जा सका। संपूर्ण दावा ट्रकों द्वारा कंटेनरीकृत कार्गो तथा सड़क परिवहन के लिए अनुमानित भाड़े के आधार पर किया गया और विशिष्ट बीजकों के संबंध में वास्तविक आंकड़ों के अभाव में अंतर बहुत अधिक प्रतीत होता है। यह पहलू भी निर्यातक को सत्यापन रिपोर्ट की मार्फत सूचित किया गया। इस निर्यातक ने अपने दावे के सबूत में और आगे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः भाड़ा तत्व की गणना औसत आधार पर की गई है और दावे किए गए अंतर को अमान्य कर दिया गया है।

38. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी का विचार है कि उनके संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण उन्हें काफी पहले सूचित उनके सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया है और निर्धारण का आधार उन्हें पर्याप्त रूप से विस्तार से बताया गया है। अतः प्राधिकारी को उनकी दलीलों में कोई गुणावगुण दिखाई नहीं देता है, जहां तक पाटन निर्धारण का संबंध है।
39. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकट पश्चात निवेदनों में तर्क दिया है कि निर्यातक के संबंध में अनुमानित पाटन मार्जिन समग्र रूप से अपर्याप्त है क्योंकि सामान्य व्यापार प्रक्रिया परीक्षण के प्रयोजनार्थ निर्यात के देश में उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा उनके लागत निर्धारण के विभिन्न पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया है कि प्रमुख कच्चे माल की लागतें काफी बढ़ गई हैं और निर्यातक द्वारा इन लागतों तथा परिवर्तन लागतों को कम आंका गया प्रतीत होता है।
40. प्राधिकारी नोट करता है कि इस मामले में समीक्षा के लिए सहयोगकारी निर्यातक तथा आवेदक के संबंध में उत्पादन लागत का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उनके आंकड़ों के सत्यापन और जहां कहीं त्रुटियां पाई गईं, उनके समायोजन के पश्चात किया गया। अतः प्राधिकारी उनकी दलीलों में कोई गुणावगुण नहीं पाता है और उपरोक्त पाटन मार्जिन की पुष्टि करता है।

च. क्षति का निर्धारण

41. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर समीक्षा की जाती रहे। इस प्रकार की समीक्षा में प्राधिकारी से यह अपेक्षा है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या पाटन जारी है और ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को ऐसे पाटन से कितनी मात्रा में क्षति हुई है और यदि ऐसे शुल्कों को समाप्त किया जाए अथवा उनमें संशोधन किया जाए तो ऐसी स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस बात का निर्धारण करते हुए कि संबद्ध देशों से संबद्ध माल का आयात भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर हो रहा है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग हुई क्षति और पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की।
42. प्राधिकारी नोट करता है कि भारतीय बाजार में संबद्ध माल का आयात कई देशों से साथ-साथ हो रहा है जिनमें संबद्ध देश शामिल हैं जिनके बारे में प्राधिकारी द्वारा जांच आरंभ की गई है। अतः, प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों जिनमें घरेलू उद्योग पर जांच में शामिल अन्य देशों से पाटित आयात शामिल है, का घरेलू उद्योग पर उनके संचयी आकलन के प्रभाव की शर्तें पूरी होती हैं।

च.1 क्षति का जारी रहना**च 1.1 इच्छुक पक्षकारों के विचार**

43. घरेलू उद्योग का तर्क है कि उसे शुल्क लगाए जाने के बावजूद संबद्ध देशों से हो रहे लगातार पाटन के कारण वास्तविक क्षति का होना जारी है। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ निवेदन किया है कि
- कि पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण से उन्हें अपना निष्पादन मामूली रूप से सुधार पाने में सहायता मिली है। लेकिन इस समीक्षा में शामिल आवेदक सहित संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा गहन पाटन किए जाने से उन्हें इस कारण कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ है।
 - कि उनकी उत्पादकता तथा उत्पादन मात्रा में सुधार के बावजूद और किए गए विभिन्न लागत कटौती उपायों के जरिए उत्पादन लागत में कटौती के बावजूद वे संबद्ध देशों सहित विभिन्न स्रोतों से जारी पाटन के कारण हुए अपनी लागत वसूल करने के लिए लाभकारी कीमतें प्राप्त करने में असफल रहे हैं।
 - कि आवेदक निर्यातक ने कच्चे माल की लागत में होने वाली वृद्धि को काफी हद तक आत्मसात किया है और उन कीमतों पर पाटन अभी भी जारी है जो यथोचित नहीं है और इस प्रकार इस कारण घरेलू उद्योग को गंदा हानि हो रही है क्योंकि घरेलू बाजार में अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए वे अपनी उत्पादन लागत से कहीं कम कीमत पर बिक्री करने को बाध्य हैं।
44. निर्यातकों तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों ने अपने विभिन्न निवेदनों में इस बात का दावा किया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं होती है। संक्षिप्तता के प्रयोजनार्थ इच्छुक पक्षकारों द्वारा अपने विभिन्न लिखित निवेदनों में उठाए गए विभिन्न तर्कों को इस जांच परिणाम में शामिल नहीं किया गया है। किंतु, अनेक निवेदनों को सारांश में नीचे दिया गया है:
- कि अपार का कार्य-निष्पादन उत्कृष्ट रहा है और उन्हें कोई क्षति होने का कोई कारणात्मक संबंध दिखाई नहीं देता है। उनके वित्तीय परिणाम यह दर्शाते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा निष्पादन करके सुधार किया है। उनके सभी आर्थिक संकेतक उनके लिए बिल्कुल ही सकारात्मक रहे हैं।
 - कि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के तुलन-पत्रों के साथ संलग्न अपार की निदेशक-रिपोर्ट में स्वयं बताया गया है कि वे अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ाकर 10,000 मी.टन प्रतिवर्ष कर रहे हैं। अपार की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ गई होती यदि वह ऊंचे स्तर पर कार्य-चालन नहीं कर रहे होते और पर्याप्त लाभ नहीं कमा रहे होते।
 - कि 15,000 टीपीए से कम की क्षमता से एनबीआर उत्पादन का विश्व-स्तर खर्चीला समझा जा सकता है जो अर्थक्षम नहीं है। अपार की उत्पादन क्षमता 4,000 टीपीए बताई गई है जोकि लागत कारगर तथा लाभ योग्य क्षमता से कहीं कम है।

- अपने कच्चे माल की सप्लाई के लिए अपार दूसरों पर निर्भर है। चूंकि कच्चे माल की कीमतें स्वभाव में बहुत ही अस्थिर होती हैं अतः उनका अपने उत्पादन पर, जो भी हो, कोई नियंत्रण नहीं है और उनके पास स्वयं को कीमत वृद्धि तथा उत्पादन हानि की मौज के अध्यधीन रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।
- अपार के उत्पादन, बिक्री तथा लाभ में कोई कमी नहीं आई है। उनकी वृद्धि दर 5% से 7% तक रही है जोकि रबड़ उद्योग की वृद्धि दर के अनुरूप है। अगले 5 वर्षों के दौरान एनबीआर की जरूरतों को देखते हुए अपार की क्षमता इस उद्योग की कुल मांग को पूरा नहीं कर सकेगी।
- उनके एक्रीलोनिट्राइल बुटाडीन रबड़ के उत्पादन तथा बिक्री में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अतः कोरिया गणराज्य, जर्मनी अथवा अन्य किसी अन्य देश से किए गए आयातों का उनके उत्पादन, बिक्री तथा लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। वास्तव में, उनकी बिक्री तथा लाभ में सतत वृद्धि बहुत अच्छी तरह से हो रही है।
- कि एनबीआर के विनिर्माण के लिए एक्रीलोनिट्राइल तथा बुटाडीन मोनोमर ही आधारित निविष्टियां होती हैं। इन निविष्टियों की कीमतों में आई तीव्र गिरावट के कारण पिछले चार वर्षों में एनबीआर की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का रुख रहा है। इस प्रकार, कोरिया गणराज्य तथा जर्मनी से किए गए एनबीआर के आयातों की कीमतों में गिरावट कोई अपवाद नहीं है।
- कि भारतीय रबड़ उद्योग को एनबीआर पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी उत्पादन लागतें पड़ोसी देशों के विनिर्माताओं की लागतों की तुलना में अपेक्षतया अधिक हैं।
- कि मात्रा-वार तथा ग्रेड वार दोनों ही दृष्टियों से उद्योग की जरूरत अपार की उत्पादन क्षमताओं की तुलना में अधिक है, अतः मांग को पूरा करने के लिए आयातों का आयात करना अनिवार्य है।
- निट्राइल रबड़ का विश्व-व्यापी उत्पादन कई ग्रेडों में होता जिनकी संख्या 50 से भी अधिक है जबकि घरेलू उत्पादक इस उद्योग को केवल 4/5 ग्रेडों की ही ऑफर करता है। अतः सभी आयातित ग्रेडों पर पाटनरोधी शुल्क का बोरा भार लगाना उचित नहीं है जबकि 90% ग्रेडों का उत्पादन देश में नहीं होता है।
- कि याचिकाकर्ता भारत में इस उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। वे प्रतिवर्ष 4,000 मी.टन एनबीआर का उत्पादन करते हैं जबकि वार्षिक खपत 10,000 मी.टन से भी अधिक है। यह ऐसे सभी दलीलों का विरोध है कि उन मात्राओं के लिए भी जिनके लिए याचिकाकर्ता के पास कोई उत्पादन क्षमता नहीं है, खपत उद्योग पाटन रोधी शुल्क का भुगतान करने को बाध्य है।
- कि अपार के वार्षिक लेखे विलयित तुलन-पत्र के रूप में हैं और उसके एनबीआर के उत्पादन, बिक्री तथा लाभप्रदता के बारे में स्पष्ट रूप से बताना बहुत ही मुश्किल है। दूसरे क्षेत्रों में अपार का समूचा व्यापार गिर रहा है और केवल एनबीआर तथा एचएसआर के क्षेत्रों में ही पर्याप्त वृद्धि होती रही है। अपार के उत्पादन, बिक्री तथा कीमतों संबंधी आंकड़े पूर्ण रूप से

अंधाधुंध चल रहे हैं। स्पष्ट रूप से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। जांच की प्रथम अवधि से लेकर अब तक के आंकड़े उनके समेकित तुलन-पत्र पर आधारित हैं जिनमें एनबीआर, एसबीआर, आदि संबंधी आंकड़े हर आदमी को जानबूझ कर भ्रमित कर रहे हैं।

45. मै0 ऋषिरूप पॉलीमर्स ने अपने निवेदन में तर्क दिया है कि भारत में पाटनरोधी उपाय अपेक्षतया कम शुल्क वाले नियम पर आधारित हैं और चूंकि क्षति मार्जिन की तुलना में पाटन मार्जिन अपेक्षतया कम पाया गया, अतः प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के आधार पर पिछली अवधि में किए गए उपायों को लागू किया, इस प्रकार घरेलू उद्योग के लिए लाभप्रदता में गिरावट को पिछली अवधि के पश्चात् पर छोड़ दिया। जहां तक क्षति मार्जिन तथा जांच अवधि की अंतिम समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन के बीच आए अंतर की सीमा का संबंध है, केकेपीसी से किए गए आयातों पर पर्याप्त लाभप्रदता के अभाव को कोई कारण नहीं माना जा सकता है और केकेपीसी से किए गए आयातों के कारण किसी भी तथाकथित क्षति पर आए प्रभाव को इसका कारण नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि ऐसे अन्य स्रोतों से आयात किए गए जिनमें पाटनरोधी उपायों के अध्यधीन लाए गए वे देश भी साथ-साथ शामिल हैं और इसलिए उन देशों से इतने ही अथवा उससे कम लैंडेड मूल्य पर किए गए आयातों के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा ध्यान में लिए जाने की आवश्यकता है जबकि वह किसी कीमत प्रभाव का निर्धारण करे। अंतिम समीक्षा तथा मध्यावधि समीक्षा जांच अवधियों के बीच की मध्यवर्ती अवधि में सीमाशुल्क में गिरावट आई है और सभी देशों से किए गए आयातों के लैंडेड मूल्यों में गिरावट का जहां तक संबंध है, कीमत प्रभाव को केकेपीसी पर नहीं थोपा जा सकता है। इस उत्पाद पर प्रारंभिक सीमाशुल्क को कम करने के संबंध में भारतीय सरकार की चुस्त कार्यवाही से घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव पड़ा है। परंतु इसका आरोप घरेलू उद्योग को पर्याप्त लाभप्रदता के अभाव के आधारस्वरूप निर्यातक पर नहीं लगाया जा सकता है।
46. उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कीमत कटौती अथवा कीमत मंदी के तत्वों का गलत तरीके से मूल्यांकन कर रहा है और इस माल के लैंडेड मूल्य के लिए निर्यातक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। केपीसी का इस माल की सीआईएफ कीमत पर ही एक मात्र नियंत्रण है जिसकी वह भारतीय आयातकों को ऑफर करता है और सीमाशुल्क अथवा विनिमय दर, इत्यादि की वजह से लैंडेड मूल्य में अंतर केकेपीसी के नियंत्रण से बाहर है और समीक्षा जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती अथवा कीमत मंदी के मूल्यांकन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे कारक केकेपीसी के ऊपर नहीं मढ़े जा सकते हैं और इन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उस समय सामान्यीकृत कर दिया जाना चाहिए जबकि इस कारक का मूल्यांकन किया जाए। यह निवेदन है कि एक बार ऐसा किए जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी यह पाएगा कि इसके लिए कोई कारण नहीं है क्योंकि समीक्षा जांच-अवधि के दौरान लागू उपाय इससे अधिक रहे हैं जो संदर्भ कीमत स्तर के

आधार पर जरूरी थे, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि अंतिम लैंडेड कीमत के कारण घरेलू उद्योग पर कोई कीमत कटौती प्रभाव पड़ा हो ।

47. उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के लगभग सभी आर्थिक तत्व सकारात्मक हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग की मुख्य शिकायत पर्याप्त लाभ की कमी के संबंध में है और यह निर्दिष्ट प्राधिकारी के ऊपर निर्भर है कि वह इसके लिए संभावित कारणों की जांच करे क्योंकि यह समीक्षा जांच-अवधि में केकेपीसी से होने वाले आयातों के कारण नहीं हुआ है ।

च.1.2 घरेलू उद्योग के विचार

48. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि इच्छुक पक्षकारों का यह दावा कि अपार इंडस्ट्रीज को कोई हानि नहीं हुई है और अपार सहित कोई भी कंपनी इतनी लम्बी अवधि में लगातार हानि उठाती रही है, सही नहीं है । उन्होंने तर्क दिया है कि ऐसा नहीं है कि घरेलू उद्योग ने हमेशा ही हानि उठाई हो अथवा अवांछित संरक्षण के लिए अनुरोध किया हो । निर्यातक द्वारा दायर क्षति संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि इस निर्यातक को इस उत्पाद के संबंध में कभी लाभ भी कमाया है ।
49. उन्होंने तर्क दिया है कि उनके पास तीन मुख्य व्यवसाय/शाखाएं हैं अर्थात् स्पेशल ऑयल, एनबीआर/एसबीआर तथा कंडक्टर । यह कंपनी स्पेशल ऑयल तथा कंडक्टरों के मामले में यथोचित रूप से अच्छा निष्पादन कर रही है । स्पेशल ऑयल तथा कंडक्टर व्यापार अपार लिमिटेड का पहले एक हिस्सा हुआ करता था और एनबीआर कार्य गुजरात अपार पॉलीमर्स लि० का हिस्सा हुआ करता था । कंपनी को एनबीआर व्यापार में लगातार हानि हो रही थी । एनबीआर व्यापार में हुई इस लगातार हानि के कारण कंपनी को अपार लिमिटेड का विलय गुजरात अपार पॉलीमर्स लि० में करने को बाध्य होना पड़ा और एनबीआर-एसबीआर प्रचालनों में स्पेशल ऑयल तथा कंडक्टरों के लाभ को बढ़ावा दिया गया । अतः अपार लिमिटेड का विलय गुजरात अपार पॉलीमर्स लिमिटेड में कर दिया गया और अपार गुजरात पॉलीमर्स लि० का नाम बदलकर अपार इंडस्ट्रीज लि० कर दिया गया । अतः घरेलू उद्योग द्वारा कृत्रिम हानि दर्शाने अथवा अपने लाभ को नहीं दिखाने संबंधी आरोप निराधार हैं ।

च.2. प्राधिकारी द्वारा जांच

50. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा अपने-अपने निवेदनों में दिए गए तर्कों को नोट किया है और घरेलू उद्योग को भी क्षति के जारी रहने के मुद्दे की जांच प्राधिकारी के समक्ष दिए गए इन तर्कों के मद्देनजर की गई है । प्राधिकारी नोट करता है कि यह शुल्क मूल रूप से मूल जांच में कोरिया तथा जर्मनी के सभी निर्यातकों के विरुद्ध संदर्भ कीमत के आधार पर

लगाया गया था । आवेदक निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारणों के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की और अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस अपीलकर्ता के संबंध में शुल्क को निर्धारित शुल्क आधार पर परिवर्तित कर दिया । यह भी संज्ञान में आया है कि इस आवेदक का मूल अनुरोध इस तथ्य को देखते हुए पाटन मार्जिन की एक सीमित समीक्षा के संबंध में था कि यह शुल्क संदर्भ कीमत आधार पर आधारिक सीमाशुल्क में कमी करने के बाद लगाया गया था और एकत्र किए जा रहे पाटनरोधी शुल्क, पाटन मार्जिन से अधिक रहा । अतः अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा नये शुल्क ढांचे की घोषणा कर दिए जाने के बाद इस आवेदक द्वारा समीक्षा का मूल आधार निष्फल हो जाता है ।

51. किंतु, आवेदकों ने अपीलीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेशों को एक याचिका के रूप में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है और प्राधिकारी को सूचित किया कि प्राधिकारी के समक्ष उनका निवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष दायर अपील के निर्णय के बिना पूर्वाग्रह है । अतः प्राधिकारी नोट करता है कि चूंकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार एक समीक्षा आरंभ कर दी गई है, जिसमें प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह इस शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता की समय-समय पर जांच करें अतः यह समीक्षा इस मामले के पाटन तथा क्षति की मात्रा और जांच के दौरान विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों को ध्यान में रखते हुए शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता की जांच करने हेतु की गई है ।
52. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि इन दोनों उद्देश्यों की जांच की जाए (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव । पाटित आयातों के मात्रा-प्रभाव के संबंध में प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि वे इस बात की जांच करें कि आयातों में संपूर्ण रूप से अथवा उत्पादन से संबंधित अथवा आयातक सदस्य में खपत की दृष्टि से क्या कोई काफी वृद्धि रही है । जहां तक पाटित आयातों के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि वे इस बात की जांच करें कि क्या आयातक देश में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के फलस्वरूप काफी सीमा तक कीमतों में अन्यथा मंदी आई है, अथवा कीमत वृद्धि में बाधा आई है जो अन्यथा काफी सीमा तक हो गई होती ।
53. मौजूदा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध माल के पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमत प्रभाव और कीमतों तथा लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति होने तथा पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों, यदि कोई हो की जांच की जा सके । इस निर्यातक का यह तर्क कि अन्य स्रोतों से घरेलू उद्योग

को क्षति हुई है और आधारिक सीमाशुल्क में कमी के मुद्दे पर भी प्राधिकारी द्वारा उसके संचयन तथा कारणात्मक संबंध और कीमत कटौती तथा कम दाम पर बिक्री का विश्लेषण भी किया गया है।

54. चूंकि सकारात्मक पाटन मार्जिन संबद्ध देशों से किए गए निर्यात के मामले में सिद्ध कर दिया गया है अतः उन देशों से होने वाले सभी निर्यातों को क्षति विश्लेषण तथा कारणात्मक संबंधों की जांच के प्रयोजनार्थ पाटित आयात माना गया है।

(क) मात्रा प्रभाव: पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

55. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा और अन्य देशों से किए गए आयातों के प्रभाव के संबंध में निम्नानुसार जांच की गई है:-

i) संबद्ध देशों की आयात मात्रा तथा हिस्सा:

56. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि एनबीआर के आयात अनेक सीमाशुल्क शीषों के तहत बताई गई है और एनबीआर को डीजीसीआईएंडएस के सौदेवार आंकड़ों से अलग करना कठिन है क्योंकि तथ्य यह है कि डीजीसीआईएंड एस के आंकड़े इस उत्पाद का पूर्ण ब्यौरा परिलक्षित नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने संगत अवधि के लिए प्लास्टिक तथा पॉलीमर समीक्षा (पीपीआर) में प्रकाशित आयात आंकड़ों पर ही विश्वास किया है। प्राधिकारी ने तुलना प्रयोजन के लिए डीजीसीआईएंडएस के सौदा-स्तर आंकड़ों और पीपीआर द्वारा प्रकाशित आयात आंकड़ों की जांच की है।

57. किंतु ऊपर उल्लिखित मूल्य ह्रास तथा वर्गीकरण समस्या की वजह से इन दोनों स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों में काफी अंतर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त डीजीसीआईएस के आंकड़ों में कोरिया से होने वाले निर्यात आंकड़ों की तुलना में वहां से होने वाले आयात बहुत कम दिखाई देते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि पीपीआर सभी पक्षों की मार्फत होने वाले आयातों के बारे में रिपोर्ट नहीं देता है। अतः क्षति के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने अन्य स्रोतों से अपने पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समायोजित डीसीआईएंडएस के आंकड़ों को अंगीकार किया है। इस निर्यातक ने अपने प्रकटन पश्चात निवेदनों में तर्क दिए हैं कि क्षति विश्लेषण के लिए ऐसे संकर आंकड़े त्रुटिपूर्ण हैं और इससे असहयोगकारी निर्यातकों को लाभ पहुंचेगा। इस संबंध में इस निर्यातक ने तर्क दिया कि करार के अनुबंध 1 के पैरा 7 और करार के अनुच्छेद 6.8 को प्राधिकारी द्वारा लागू नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करता है कि राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी में कतिपय आयात को सही-सही शामिल नहीं किया गया है क्योंकि आयात के समय गलत वर्गीकरण हो गया था। अतः जहां तक हो सका प्राधिकारी के पास अन्य स्रोतों से गलत वर्गीकृत आयात आंकड़ों को उपलब्ध कराया गया और उनका प्रयोग इस

जांच के प्रयोजनार्थ कुल आयातों के यथोचित आंकलन के लिए किया गया है। अधिक से अधिक यह आंकलन संबद्ध माल के आयातों का एक रूढ़ीवादी आंकलन होता है और इसमें निर्यातक के हित के प्रांत कोई पूर्वाग्रह नहीं है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़े नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं -

मात्रा: मैट्रिक टन में

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
आयात				
कोरिया	2080	2320	2590	2870
जर्मनी	144	43	36	10
संबद्ध देशों से पाटित आयात	2224	2362	2625	2879
प्रवृत्ति	100	106	118	130
ईयू, ब्राजील, मैक्सिको (पाटित आयात)	633	847	1709	2094
शुल्क आकर्षक अन्य देश (पाटित आयात)	356	494	484	553
सभी स्रोतों से पाटित आयात	3213	3703	4818	5526
प्रवृत्ति	100	115	150	172
अन्य अपाटित आयात	0	118	217	173
योग	3213	2821	5034	5699
प्रवृत्ति	100	119	157	177

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

58. ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से किए गए पाटित आयातों में इस तथ्य के बावजूद आधार वर्ष से 30% तक की वृद्धि हुई है कि इन देशों से किए गए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क पहले ही लगा हुआ है। सभी स्रोतों से संचयी पाटित आयातों से इसी अवधि में 70% से भी अधिक वृद्धि परिलक्षित होती है। प्राधिकारी नोट करता है कि यूरोपीय संघ, ब्राजील, मैक्सिको तथा कोरिया गणराज्य के विरुद्ध ऐसे ही उत्पाद के संबंध में की जा रही एक समानांतर जांच में इन देशों/क्षेत्रों से होने वाले आयातों को पाटित आयात समझा गया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के प्रयोजनार्थ इन देशों से किए गए आयातों को पाटित आयात माना गया है। यह भी नोट किया जाता है कि ताइवान तथा जापान से होने वाले आयातों पर शुल्क लागू है। अतः सभी स्रोतों से होने वाले पाटित आयातों को मात्रा विश्लेषण के प्रयोजनाथ संचित किया गया है।

ii) मांग, उत्पादन तथा बाजार हिस्से

क) घरेलू उद्योग का उत्पादन

क्षमता तथा उत्पादन

मात्रा: एमटी

	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
प्रतिस्थापित क्षमता(एनबीआर)	6,250	8,350	8,800	8,800
सूचीकृत	100	134	141	141
कुल उत्पादन(एनबीआर)	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत	100	130	130	142
सकल उत्पादन (एनबीआर गांठ केवल)	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत	100	123	121	130
क्षमता उपयोग% (एनबीआर)	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत	100	97	92	101

59. घरेलू उद्योग के उत्पादन आंकड़ों से विदित होता है कि वर्ष 2001-02 और उसके बाद क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। किंतु, क्षमता में यह वृद्धि मुख्य रूप से मौजूदा क्षमता में अवरोध समाप्त होने के कारण हुई है। घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष की तुलना में अपने उत्पादन में सुधार किया है। क्षमता उपयोग में भी मामूली सुधार हुआ है। किंतु, क्षमता वृद्धि तथा उत्पादन की भी घरेलू उद्योग में मांग की वृद्धि और घरेलू बाजार में बिक्री हेतु घरेलू उद्योग की सामर्थ्य के संदर्भ में जांच किए जाने की आवश्यकता है।

60. यह संज्ञान में आया है कि भारत में एनबीआर की मांग में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि सतत सकारात्मक मांग संचलन को देखते हुए उन्होंने अपनी क्षमता में संयंत्र क्षमता की बाधा हटाकर वृद्धि की थी जिसमें उन्होंने **** करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया और अपनी क्षमता को 6250 मी.टन से बढ़ाकर 8800 मी.टन कर दिया। किंतु वे अपेक्षित अधिक मांग होने के बावजूद अपनी बिक्रियों में वृद्धि करने की अपनी सामर्थ्य नहीं होने के परिणामस्वरूप क्षमता में वृद्धि के समानुपात अपने उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सके हैं। इसके परिणामस्वरूप उसके क्षमता उपयोग में सुधार नहीं हुआ है और यह अनुकूल से कम स्तर पर रहा है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि प्रतिकूल एनबीआर कार्यों के परिणामस्वरूप इस संयंत्र का उपयोग गैर-एनबीआर उत्पादों के उत्पादन

के लिए किया गया है ताकि वे निर्धारित ऊपरी खर्चा लागतों का हिस्सा पुनः प्राप्त कर सकें ।

61. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उत्पादक की क्षमता में वृद्धि अधिकांशतया अवरोधक समाप्त करने की प्रक्रिया की मार्फत हुई है ने कि क्षमता में प्रमुख वास्तविक वृद्धि के कारण । क्षमता में यह वृद्धि इस उत्पाद की मांग में होने वाली वृद्धि के अनुरूप रही जैसाकि उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है । इस संयंत्र के उत्पादन तथा क्षमता उपयोग से यह परिलक्षित होता है कि उसमें भी ऐसा ही रुख रहा है । लेकिन मांग में अच्छी खासी वृद्धि के बावजूद क्षमता का एक हिस्सा अभी भी अप्रयुक्त रह गया है । किंतु उसी अवधि के दौरान इस उत्पाद की बिक्रियों के साथ-साथ जांच से संबंधित उत्पादन तथा क्षमता उपयोग से यह इंगित होता है कि घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां मांग तथा उत्पादन के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाई हैं जिसके परिणामस्वरूप माल सूची बढ़ गई ।

ख) घरेलू उद्योग की बिक्रियां

मात्रा:मी.टन

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	जन.03 से दिस. 03
प्रारंभिक स्टॉक	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत	100	42	145	78
उत्पादन	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत	100	123	121	130
घरेलू बिक्रियां	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत	100	114	118	127
निर्यात बिक्रियां	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत	100	136	138	147
कैप्टिव खपत	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत	100	80	98	96
अन्तिम स्टॉक	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत	100	341	315	213

62. उपरोक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हालांकि आधार वर्ष की तुलना में उत्पादन में लगभग 30% की वृद्धि और विगत वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि रही है लेकिन घरेलू बिक्रियों में 27% की वृद्धि और तदनुरूपी वर्षों में 9% की वृद्धि रही है । बिक्रियों में प्रमुख वृद्धि निर्यात भाग में हुई है हालांकि निर्यात मात्रा कम रही है ।

ग) मांग तथा बाजार हिस्सा

मात्रा: मी.टन में

आयात				
कोरिया	2080	2320	2590	2870
जर्मनी	144	43	36	10
संबद्ध देशों से आयात	2224	2362	2625	2879
प्रवृत्ति	100	106	118	130
शुल्क आकर्षक अन्य देश	356	494	484	553
अन्य	633	965	1925	2267
कुल अन्य	989	1459	2409	2820
कुल आयात	3213	3821	5034	5699
प्रवृत्ति	100	119	157	177
घरेलू बिक्रियां	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत	100	114	118	127
कैप्टिव खपत	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत	100	80	98	96
मांग				
सूचीकृत	100	114	131	144
मांग में हिस्सा				
घरेलू उद्योग	54.39%	54.77%	48.97%	48.03%
संबद्ध देश	26.41%	24.70%	23.71%	23.74%
अन्य	11.74%	15.26%	21.76%	23.25%
कैप्टिव खपत	7.46%	5.28%	5.56%	4.99%
मांग में आयातों का कुल हिस्सा	38.15%	39.95%	45.47%	46.99%

63. विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग में आधार वर्ष से लगभग 47% की वृद्धि रही है लेकिन कुल मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा इसी अवधि के दौरान 55% से घटकर 48% रह गया। संबद्ध देशों से हुए आयातों के हिस्से में भी मामूली गिरावट रही है हालांकि समग्र रूप में काफी वृद्धि रही है। किंतु सभी आयातों के हिस्सों तथा सभी स्रोतों से किए गए पाटित आयातों के हिस्से में संबद्ध देशों तथा कतिपय अन्य देशों के विरुद्ध लागू शुल्क बावजूद काफी वृद्धि रही है। इन आंकड़ों से परिलक्षित होता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा बिक्रियों में वृद्धि के बावजूद उसने काफी बाजार हिस्सा गंवा दिया है।

(ख) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

64. संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर आए प्रभाव की कीमत कटौती, कम दाम पर बिक्री कीमत, कीमत मंदी तथा कीमत दबाव, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन की भारित औसत लागत, भारित औसत निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और अक्षतिकारी कीमत (एनआईपी) (जिसकी गणना घरेलू उद्योग की लागत निर्धारण जानकारी का नियमन करने के बाद की गई है) की तुलना संबद्ध देशों से किए गए आयातों की लैंडेड लागत से की गई है।

(i) कीमत कटौती तथा कम दाम पर बिक्री के प्रभाव

मूल्य: रु०/एम.टी.

कीमत कटौती तथा कम दाम पर बिक्री					
विवरण		2000-01	2001-02	2002-03	जन. 03 से दिस. 03
उत्पादन लागत	रु./मी.टन	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	सूचीकृत	100	82	90	94
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	*****	*****	*****	*****
प्रवृत्ति	सूचीकृत	100	99	92	96
लैंडेड मूल्य (संबद्ध देश) (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रु./मी.टन	*****	*****	*****	*****
लैंडेड मूल्य (संचयी)	रु./मी.टन	*****	*****	*****	*****
कीमत वचन (संबद्ध देश)	रु./मी.टन	*****	*****	*****	*****
कीमत कटौती (संचयी)	रु./मी.टन	*****	*****	*****	*****
% कीमत कटौती (संबद्ध देश)		0-15%	5-15%	0-15%	5-20%
कीमत कटौती (संचयी)	रु./मी.टन	0-10%	0-10%	नकारात्मक	5-15%
अक्षतिकारी कीमत	रु./मी.टन				*****
कम कीमत पर बिक्री कीमत (संबद्ध देश)					*****
कम कीमत पर बिक्री (संचयी)	रु./मी.टन				*****
कम कीमत पर बिक्री (संबद्ध देश)	%				5-20%
कम कीमत पर बिक्री % (संचयी)					5-15%

65. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (निवल बिक्री वसूली) काफी गिरावट दर्शाती है हालांकि वर्ष 2001-02 में काफी गिरावट दर्शाने के बाद उसकी उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण उत्पादन लागत को वसूल करने के उद्देश्य से अपनी कीमतें लाभकारी स्तर तक बढ़ाने में असमर्थ रहा है।
66. कीमत कटौती का निर्धारण संपूर्ण जांच-अवधि के लिए संबद्ध देशों से किए गए पाटित आयातों के भारित औसत लैंडेड मूल्य की तुलना उसी अवधि के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री वसूली से करने के बाद किया गया है। इस प्रयोजनार्थ आयातों के लैंडेड मूल्य की गणना 1% हैंडलिंग प्रभारों को जोड़कर तथा संबद्ध देश की आयात कीमतों के डीजीसीआईएस आंकड़ों में बताए गए मूल्य में लागू आधारिक सीमाशुल्क को जोड़कर की गई है।
67. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के निर्धारण में घरेलू उद्योग द्वारा ऑफर की गई छूटों, कटौतियों तथा कमीशनों और भुगतान किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट दी गई है।
68. कम दाम पर बिक्री कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से किए गए आयातों की भारित औसत लैंडेड कीमत की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की अक्षतिकारी बिक्री कीमत और शेष वर्षों के लिए उत्पादन लागत से की गई है।
69. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध देशों से हुए आयात घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की तुलना में काफी कम रहे हैं। इस प्रकार, कीमत में काफी कटौती हुई है। कीमत कटौती तथा कम दाम पर बिक्री कीमत (लागू पाटनरोधी शुल्क पर ध्यान दिए बिना) पर्याप्त पाई गई है। प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध माल का पाटन कतिपय अन्य देशों से साथ-साथ हो रहा है जिनके संबंध में जांच चल रही है और सभी स्रोतों से किए गए पाटित आयातों के कीमत प्रभाव की जांच संचयी आधार पर की जा रही है। ऐसे सभी स्रोतों से किए गए पाटित आयातों की वजह से घरेलू कीमतों पर कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री के प्रभाव काफी पाए गए हैं।

(ii) पाटित आयातों के कीमत दबाव तथा मंदी संबंधी प्रभाव

70. पाटित आयातों के कीमत दबाव के प्रभाव की संबद्ध देशों की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली तथा लैंडेड मूल्यों के संदर्भ में भी जांच की गई है।
71. संबद्ध माल की उत्पादन लागत से वर्ष 2001-02 में काफी गिरावट दर्शाए जाने के बाद पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित होती है। उत्पादन लागत में यह वृद्धि कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण पर्याप्त है जो उत्पादन लागत का एक प्रमुख अंग होती है। किंतु, बिक्री

कीमत में तदनुसूची अवधि के दौरान गिरावट दर्शाई गई है जिससे संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के मूल्य प्रभाव के कारण पूरी लागत वसूल करने के लिए अपनी कीमत बढ़ाने में घरेलू उद्योग ने असमर्थता दर्शाई है।

72. इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि अन्य पाटित स्रोतों के आयातों की कीमत प्रभाव की भी कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री के प्रभावों के संबंध में भी जांच की जानी चाहिए। किंतु प्राधिकारी नोट करता है कि सभी पाटित स्रोतों के आयातों को क्षति की जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग पर मात्रा तथा कीमत दोनों दृष्टियों से संचयी किया गया है क्योंकि इन स्रोतों से किए गए आयात समान वस्तुएं हैं जो उसी समयावधि के दौरान उन्हीं माध्यमों के जरिए भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही हैं और उसी बाजार में घरेलू उत्पादों से परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। संचयी आयातों से घरेलू कीमतों पर कीमत कटौती तथा कम दाम पर बिक्री संबंधी प्रभाव प्रदर्शित होता है।

च.3 अन्य क्षति कारकों की जांच

73. प्राधिकारी ने बिक्रियों में वास्तविक तथा संभावित गिरावट, क्षमता तथा क्षमता उपयोग में वास्तविक तथा संभावित गिरावट, उत्पादन में वास्तविक तथा संभावित गिरावट और बाजार हिस्सों, इत्यादि जैसे कारकों की पूर्ववर्ती भाग में जांच की है जिसमें यह इंगित किया गया कि हालांकि बिक्रियों तथा उत्पादन में वास्तविक रूप से कोई गिरावट नहीं रही अतः उत्पादन तथा बिक्रियों में वृद्धि देश में मांग में बहुत भारी वृद्धि को देखते हुए संभावित वृद्धि से कहीं कम रही है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि अच्छी मांग के बावजूद बाजार हिस्से में वास्तविक गिरावट में गिरावट आई है और आयात की मात्रा आगे यह इंगित करती है कि बाजार हिस्से में और आगे गिरावट की संभावना है। इन कारकों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने उन अन्य आवश्यक आर्थिक कारकों तथा सूचियों की जांच की है जिनका उद्योग की स्थिति से संबंध होता है और यह निम्नानुसार है:-

i) उत्पादकता में वास्तविक तथा संभाव्य गिरावट

विवरण	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	जन.03 से दिस. 03
उत्पादकता	प्रति कर्मचारी	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत		100.00	124.18	124.35	138.69
उत्पादकता	मी.टन/प्रतिदिन	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत		100	123.21	120.54	130.22

उत्पादकता प्रति दिन -(एक वर्ष में उत्पादन के 360 दिन मानकर)

जांच की है जिसमें यह इंगित किया गया कि हालांकि बिक्रियों तथा उत्पादन में वास्तविक रूप से कोई गिरावट नहीं रही अतः उत्पादन तथा बिक्रियों में वृद्धि देश में मांग में बहुत भारी वृद्धि को देखते हुए संभावित वृद्धि से कहीं कम रही है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि अच्छी मांग के बावजूद बाजार हिस्से में वास्तविक गिरावट में गिरावट आई है और आयात की मात्रा आगे यह इंगित करती है कि बाजार हिस्से में और आगे गिरावट की संभावना है। इन कारकों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने उन अन्य आवश्यक आर्थिक कारकों तथा सूचियों की जांच की है जिनका उद्योग की स्थिति से संबंध होता है और यह निम्नानुसार है:-

i) उत्पादकता में वास्तविक तथा संभाव्य गिरावट

विवरण	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	जन.03 से दिस. 03
उत्पादकता	प्रति कर्मचारी	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत		100.00	124.18	124.35	138.69
उत्पादकता	मी. टन/प्रतिदिन	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत		100	123.21	120.54	130.22

उत्पादकता प्रति दिन -(एक वर्ष में उत्पादन के 360 दिन मानकर)

74. घरेलू उद्योग की उत्पादकता को उसके उत्पादन की श्रमिक उत्पादकता और दैनिक उत्पादन के रूप में मापा जाता है और यह संज्ञान में आया है कि उत्पादकता में काफी सुधार आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्योग ने लागत कटौती करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के वास्ते अपनी उत्पादकता में सुधार करने का प्रयास किया है। किंतु, इस सुधरी हुई उत्पादकता के परिणामस्वरूप लाभप्रदता नहीं हुई है क्योंकि उसकी बिक्रियों की वसूली कम रही है।

ii) नकद प्रवाह पर लाभ तथा वास्तविक एवं संभाव्य प्रभाव

75. प्राधिकारी ने प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों में कंपनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन के संबंध में इच्छुक पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग के तर्कों को नोट किया है। किंतु यह भी नोट किया जाता है कि मौजूदा जांच एक बहु-उत्पाद कंपनी द्वारा विनिर्मित किसी विशेष उत्पाद के संबंध में है और क्षति संबंधी जांच विचाराधीन

74. घरेलू उद्योग की उत्पादकता को उसके उत्पादन की श्रमिक उत्पादकता और दैनिक उत्पादन के रूप में मापा जाता है और यह संज्ञान में आया है कि उत्पादकता में काफी सुधार आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्योग ने लागत कटौती करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के वास्ते अपनी उत्पादकता में सुधार करने का प्रयास किया है। किंतु इस सुधरी हुई उत्पादकता के परिणामस्वरूप लाभप्रदता नहीं हुई है क्योंकि उसकी बिक्रियों की वसूली कम रही है।

ii) नकद प्रवाह पर लाभ तथा वास्तविक एवं संभाव्य प्रभाव

75. प्राधिकारी ने प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों में कंपनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन के संबंध में इच्छुक पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग के तर्कों को नोट किया है। किंतु यह भी नोट किया जाता है कि मौजूदा जांच एक बहु-उत्पाद कंपनी द्वारा विनिर्मित किसी विशेष उत्पाद के संबंध में है और क्षति संबंधी जांच विचाराधीन उत्पाद के घरेलू प्रचालन और अन्य बाहरी कारकों, यदि कोई हों के कारण क्षति तक ही सीमित है।

विवरण	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	जन.03 से दिस. 03
बिक्री लागत	रु./मी.टन	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत		100	85.44	91.0	96
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत		100	98.85	92.4	96
लाभ/हानि	रु./मी.टन	(*****)	*****	(*****)	(*****)
सूचीकृत		(100)	19.03	(48.03)	(94.70)
घरेलू बिक्रियों पर कुल लाभ/हानि	लाख रु.	(*****)	*****	(*****)	(*****)
सूचीकृत		(100)	55.46	(84.58)	(113.15)
मूल्यहास	लाख रु.	*****	*****	*****	*****
सूचीकृत		(100)	100.09	96.49	90.43
एनबीआर से नकद लाभ/हानि	लाख रु.	(****)	****	(****)	(****)
सूचीकृत		(100)	325.69	(63.89)	(152.61)

76. इस कारक की जांच से विदित होता है कि हालांकि घरेलू उद्योग के कुल राजस्व तथा नकद प्रवाह में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू प्रचालनों से घरेलू उत्पादन तथा बिक्रियों में वृद्धि के कारण सुधार हुआ है लेकिन इस उद्योग को कम होती जा रही प्रति इकाई वसूली के कारण जांच अवधि के दौरान उसके घरेलू प्रचालनों से इस उत्पाद में हानि का होना जारी है। यह उद्योग पाटित आयातों के मौजूदा कीमत स्तर के कारण अपनी लागत वसूल करने हेतु एक उचित कीमत वसूल नहीं कर पाया है। केवल वह वर्ष जिसमें घरेलू उद्योग को एक बहुत अच्छा लाभ मार्जिन प्राप्त हुआ, वर्ष 2001-02 रहा है। अतः संबद्ध माल के संबंध में कंपनी का वित्तीय कार्य-निष्पादन कम प्रति इकाई वसूली के मुख्य कारण से खराब रहा है।

iii) रोजगार तथा मजदूरियों पर वास्तविक तथा संभाव्य प्रभाव

77. रोजगार के स्तर में मामूली गिरावट रही है। लेकिन वेतन तथा मजदूरियों के कारण खर्चों में लगभग 14% की वृद्धि रही है। किंतु वेतन तथा मजदूरी के व्यय में वृद्धि तुलनीय अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप आगे-पीछे है।

विवरण	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	जन.-दिस. 03
रोजगार					
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीकृत	100	104.51	104.51	102.26
मजदूरियां		****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	107.94	113.79	116.32
प्रति कर्मचारी मजदूरी	लाख रु.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीकृत	100	103.28	108.88	113.76

iv) पूंजी निवेश पर आय और पूंजी बढ़ाने की सामर्थ्य

78. घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर आय में आधार वर्ष तथा पिछले वर्षों की तुलना में ह्रास दर्शाया गया है।

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	जन.-दिस. 03
लगाई गई पूंजी- एनएफए + कार्यशील पूंजी	****	****	****	****
सूचीकृत	100.00	96.33	101.84	95.51
लाभ	(****)	****	(****)	(****)
सूचीकृत	(100.00)	55.46	(84.58)	(113.15)
व्याज	****	****	****	****
सूचीकृत	100.00	120.79	106.48	85.35
पीबीआईटी	****	****	****	****
सूचीकृत	100.00	445.27	146.79	34.18
लगाई गई पूंजी पर आय-एनएफए + कार्यशील पूंजी	****	****	****	****
सूचीकृत	100	462.23	144.14	35.78

v) **पूंजी तथा पूंजी निवेश लेने की सामर्थ्य**

79. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता मौजूदा क्षमता में अवरोध हटाकर 6250 मी.टन से बढ़ाकर 8800 कर दी जिसमें वर्ष 2001-02 जिसमें उसे इस उत्पाद खंड में निवल लाभ हुआ था, के दौरान **** करोड़ ₹ का पूंजी निवेश किया गया था। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कोई और नया पूंजी निवेश नहीं किया गया है और जैसाकि उन्होंने निवेदन किया है, उनकी और आगे पूंजी निवेश करने की कोई योजना भी नहीं है।

vi) **पाटन की मात्रा**

80. पाटन की मात्रा उस संकेतक के रूप में जितना कि घरेलू उद्योग को पाटित आयात क्षति पहुंचा सकते हैं, से यह परिलक्षित होता है कि जांच अवधि के लिए उक्त नाम के देशों के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन काफी है जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू हैं

vii) **घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक**

81. लागत ढांचे में परिवर्तन, यदि कोई हो, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्थापनों से प्रतिस्पर्धा की कीमतों की पाटित आयातों से इतर कारकों के विश्लेषण के प्रयोजन से जांच की गई है जिनसे घरेलू बाजार की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध देशों से आयातित माल का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत कटौती हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि इस उत्पाद का कोई अर्थक्षम प्रतिस्थापन नहीं है और मैसर्स अपार इंडस्ट्री ही भारत में संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है, अतः घरेलू प्रतिस्पर्धा से कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
82. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि एक दूसरे के साथ और घरेलू उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले अनेक स्रोतों से पाटित आयातों की वजह से घरेलू बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिनके संबंध में संचयी क्षति विश्लेषण किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि इस उत्पाद की घरेलू बाजार में अच्छी मांग है।
83. एनबीआर के उत्पादन के लिए एक्रिलोनिट्राइट और बुटाडीन दो प्रमुख कच्चा माल हैं। इन दोनों मोनोमर्स की कीमतों में विश्वव्यापी वृद्धि हुई है। कीमतों में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के संबंध में उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। किंतु, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में क्षति अवधि के दौरान गिरावट रही है।

viii) मालसूची

विवरण	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	जन.- दिस. 03
माल-सूची-अवधि के अंत में	मी.टन	****	****	****	****
सूचीकृत	%	100	341	315	213
उत्पादन के % के रूप में माल-सूची		**** %	**** %	**** %	**** %
प्रवृत्ति	सूचीकृत	100	276.85	261.61	163.95

84. उपरोक्त आंकड़े इंगित करते हैं कि मालसूची में पूर्ण रूप से तथा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में माल सूची में मामूली वृद्धि रही है।

च.4 अन्य ज्ञात कारक तथा कारणात्मक संबंध

85. निर्यातक/आयातक तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पाटित आयातों से इतर कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस निर्यातक ने तर्क दिया है कि चूंकि कि पाटनरोधी शुल्क कम शुल्क के सिद्धांतों पर आधारित होता है। अतः उस देश के मूल सीमाशुल्क ढांचे में परिवर्तन के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो, का कारण संबंध देशों, विशेष रूप से कोरिया से हुए पाटित आयात नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि चूंकि आयात ऐसे अनेक देशों से हो रहे हैं जहां यह शुल्क पहले ही लगा हुआ है अथवा इन आयातों के प्रभाव के तथाकथित पाटन के लिए वे जांच में शामिल हैं, अतः उनकी जांच होनी चाहिए और यह क्षति कोरिया से होने वाले आयातों के कारण नहीं हो सकती है।
86. प्राधिकारी का विचार है कि चूंकि प्राधिकारी ने अपेक्षतया कम शुल्क वाले सिद्धांत को लागू किया है, अतः यह शुल्क केवल पाटन की सीमा तक ही सीमित रहेगा और यदि सीमाशुल्क की कटौती द्वारा क्षति होती है तो इससे तब तक शुल्क स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि पाटन कुल क्षति से अधिक नहीं होगा। जहां तक अन्य स्रोतों से हुए आयातों के कारण का संबंध है, प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ वह सभी पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमत प्रभावों की संचयी जांच की है क्योंकि पाटित आयात भारतीय बाजार में विभिन्न स्रोतों से साथ-साथ प्रवेश कर रहे हैं जोकि जांच के अधीनस्थ हैं।
87. हालांकि इच्छुक पक्षकारों ने अन्य ज्ञात कारकों के बारे में कोई खास तर्क नहीं दिया है, लेकिन प्राधिकारी ने करार के अनुसार अश्रेयकर कारकों की जांच की है जोकि निम्नानुसार है:-

i) अन्य स्रोतों से हुए आयातों की मात्रा तथा कीमतें

88. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों के अलावा आयात अनेक अन्य देशों से भी हुए हैं जिनमें जापान तथा चीनी ताइपेई शामिल हैं जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। इन आंकड़ों में यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर), ब्राजील तथा मैक्सिको से हुए आयातों में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित होती है जिनके संबंध में एक अलग से जांच चल रही है और प्राधिकारी के प्रारंभिक निर्धारण से इन देशों से हुए पर्याप्त पाटन को इंगित करता है। अतः सभी पाटित स्रोतों से हुए आयातों की संचयी आधार पर जांच की गई है ताकि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके।

ii) मांग में कमी और/अथवा खपत के पैटर्न में बदलाव

89. विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग से जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में लगभग 47% की बहुत बड़ी वृद्धि परिलक्षित होती है। घरेलू बाजार में इस उत्पाद के खपत पैटर्न में कोई ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देता है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण बन सकता है।

iii) व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

90. संबद्ध माल मुक्त रूप से आयात योग्य होता है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां नहीं होती हैं। मैसर्स अपार इंडस्ट्रीज लि० ही देश में संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है। संबद्ध देशों के आयात अनेक देशों से होते हैं जो घरेलू उत्पादक के साथ प्रतिस्पर्धा दिखाते हैं। विभिन्न स्रोतों से हुए आयातों का अधिकांश भाग का निर्धारण या तो पाटित आयातों से किया गया है अथवा पाटन के दोषारोपण से संबंधित जांच में शामिल उत्पाद से होता है। अतः प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उत्पादक संबद्ध देशों सहित अनेक देशों से होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है और घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति का कारण इस तरह व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां अथवा विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है।

iv) प्रौद्योगिकी का विकास तथा निर्यात निष्पादन

91. संबद्ध देशों के सहयोगकारी विदेशी उत्पादक की उत्पादन सुविधाओं की भी पड़ताल की गई और यह देखा गया कि वे उत्पादक एकसमान उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। वास्तव में, विश्व में अधिकांश उत्पादक गुडइयर जैसे प्रौद्योगिकी अग्रणीय कंपनियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। अतः प्रौद्योगिकी विकास अथवा घरेलू उद्योग की उत्पादन की अकुशल पद्धति को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

92. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग का विचाराधीन उत्पाद का बहुत ही कम निर्यात कारोबार होता है हालांकि इसमें जांच अवधि के दौरान सतत वृद्धि दर्शाई गई है। अतः घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन कम महत्व का है और इससे घरेलू उद्योग के निष्पादन में कोई ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

v) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

93. श्रमिक उत्पादन तथा दैनिक उत्पादन की दृष्टि से घरेलू उद्योग की उत्पादकता में काफी सुधार हुआ परिलक्षित होता है। इसलिए उत्पादकता ऐसा कारक नहीं होता है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण बन सके। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने उत्पादकता में सुधार करके अपने घरेलू कार्यचालन में होने वाली क्षति को कम करने का प्रयास किया है।

च.5 क्षति की मात्रा तथा क्षति मार्जिन

94. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अक्षतिकारी कीमत की तुलना क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्यातों की लैंडेड मूल्य से की गई है। संबद्ध देशों से हुए निर्यातों की भारित औसत लैंडेड कीमत और क्षति मार्जिन पर्याप्त पाए गए हैं। घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन पश्चात निवेदन में अनुरोध किया है कि उनकी अक्षतिकारी कीमत का निर्धारण अपेक्षतया कम स्तर पर किया जाए क्योंकि कच्चे माल की लागत, सुविधाओं तथा यथोचित लाभ-मार्जिन सहित विभिन्न कारकों का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से किए गए निवेदनों को नोट कर लिया है और उसका विचार है कि एनआईपी का निर्धारण विस्तृत लागत सत्यापन तथा मानकीकरण के पश्चात किया गया है, अतः उनके तर्कों में कोई गुणावगुण नहीं पाया गया है।

छ. पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

95. इस समीक्षा के आवेदक ने तर्क दिया है कि चूंकि समीक्षा जांच अवधि में घरेलू उद्योग को क्षतिकारी पाटन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या इस क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है यदि उपाय हटा दिए जाएं। आवेदक ने तर्क दिया है कि इस कारक का मूल्यांकन किए जाने के लिए घरेलू उद्योग को चाहिए था कि वह संबद्ध देशों से हुए आयातों की संभाव्य मात्रा के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता, यदि उपाय समाप्त कर दिए जाते और ऐसी संभाव्य कीमतें जिन पर यह आयात होते और इन आयातों का उनके कार्य-चालन पर संभाव्य प्रभाव जिनके कारण निकट भविष्य में क्षति की पुनरावृत्ति होती। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि अलग-अलग अंतर वाली शुल्क पद्धति पर आधारित समीक्षा जांच-

अवधि सहित पिछले 20 महीनों के दौरान लागू पाटनरोधी उपाय पाटन, यदि कोई है से कहीं अधिक रहा है और घरेलू उद्योग को अपेक्षा से कहीं अधिक संरक्षण दिया गया । अतः उनकी मौजूदा क्षति उक्त पाटित आयातों के कारण नहीं हो सकती ।

96. आवेदक निर्यातक ने आगे यह भी निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा किया गया एकमात्र दावा यह है कि पाटन की भावी संभावना के संबंध में निर्यातक देशों से पर्याप्त मुक्त रूप से प्रयोज्य क्षमता मौजूद है जोकि बिना किसी सबूत के एक सामान्य वक्तव्य है और निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पर विश्वास नहीं कर सकता है । घरेलू उद्योग को चाहिए कि वह इस संबंध में अपना दावा बनाए रखने के लिए सख्त तथा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करे । उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि उनकी उत्पादन क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग होता है और उनके पास भारत को एनबीआर के निर्यात के लिए न तो पर्याप्त प्रयोजक क्षमता है और न ही उनके पास भारत में प्रयोज्य माल की कोई असाधारण माल सूची ही है । घरेलू उद्योग का यह दावा कि उनके पास एनबीआर उद्योग की 36,000 मी.टन प्रतिस्थापित उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, इस उन्होंने कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है बल्कि यह मात्र एक वक्तव्य है । इसके अलावा, तर्क के प्रयोजनार्थ निवेदन है कि यदि कोरिया में ऐसी कोई उत्पादन क्षमता मौजूद है तब भी इस अर्थ यह नहीं है कि यह क्षमता भारतीय बाजार की ओर भेजे जाने के लिए उपलब्ध हो । इस प्रकार भविष्य में क्षतिकारी पाटन की संभावना के लिए ऐसा अंधाधुंध आरोप पर्याप्त नहीं हो सकता है । घरेलू उद्योग को चाहिए था कि वे इस संबंध में अपना दावा कायम रखने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करते । उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि विश्व में कहीं भी एनबीआर के लिए केकेपीसी के विरुद्ध पाटनरोधी उपाय नहीं किया गया है जिससे कि केकेपीसी अपना माल ऐसे देश से भारतीय बाजार की ओर विविधीकृत करता ।
97. इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति के लिए संभावना परीक्षण इस प्रकार के मद्देनजर आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया है कि धारा 9क(5) अंतिम समीक्षा के बारे में है ने कि मध्यावधि समीक्षा के बारे में और नियम 23 की किसी मध्यावधि समीक्षा में पाटन तथा क्षति के लिए संभावना परीक्षण की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने निवेदन किया है कि अन्य देशों के कानूनों का संदर्भ असंगत है क्योंकि वे पाटनरोधी शुल्क को हटा देने की स्थिति के संबंध में है जबकि मौजूदा स्थिति पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने के बारे में है । उनके विचार में अंतिम समीक्षा तथा मध्यावधि समीक्षा के तहत परीक्षण तथा अपेक्षाएं एकसमान नहीं हैं और न ही उनका परस्पर प्रयोग ही हो सकता है, यदि मध्यावधि तथा अंतिम समीक्षा के मूल प्रयोजन तथा आशय में बहुत ज्यादा अंतर हो ।
98. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि कोरिया के निर्यातक द्वारा भारतीय बाजार में माल का पाटन करना जारी है और संबद्ध देशों से पाटन जारी है । इसके अलावा, केकेपीसी, कोरिया तथा जर्मनी के अन्य उत्पादकों की क्षमताएं उनकी घरेलू बिक्रियों/मांग से कहीं

अधिक हैं। घरेलू तथा आयातित माल के बीच कीमत अंतर अधिक रहने और भारतीय बाजार के बहुत ही अधिक कीमत संवेदनशील होने के कारण ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त भी किए जाते हैं तो भी संबद्ध देशों से होने वाले आयातों में वृद्धि क्यों न हो।

99. प्राधिकारी विभिन्न इच्छुक पक्षकारों के तर्कों को नोट करता है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 में यह उपबंध है कि-

प्राधिकारी जहां कहीं आवश्यक हो, अपनी पहल पर अथवा अन्यथा लगे हुए शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे बशर्ते निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद यथोचित समयावधि समाप्त हो गई हो, अथवा ऐसे किसी इच्छुक पक्षकार के अनुरोध पर किया जा सकेगा जो किसी समीक्षा की आवश्यकता के लिए पुष्ट सकारात्मक जानकारी प्रस्तुत करे। इच्छुक पक्षकारों का प्राधिकारियों से यह अनुरोध करने का अधिकार होगा कि वे इस बात की जांच करें कि क्या पाटन को समाप्त करने के वास्ते लगाए गए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है, क्या यदि यह शुल्क समाप्त किया जाता है अथवा उसमें कमी बेशी की जाती है अथवा दोनों ही कार्यवाही की जाती है तो ऐसी स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। यदि इस पैराग्राफ के तहत की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप प्राधिकारी इस बात का निर्धारण करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की और आगे कोई आवश्यकता नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह शुल्क तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

100. नियम 23 में प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह इस शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता की समय-समय पर जांच करें जिसमें शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन तथा क्षति की दोनों ही संभावित स्थिति का मूल्यांकन भी शामिल है। अतः प्राधिकारी ने पाटन तथा क्षति दोनों के मौजूदा तथा संभाव्य पहलुओं दोनों की जांच की है।

101. घरेलू उद्योग ने अपने उपरोक्त निवेदनों के होते हुए भी विभिन्न देशों में समीक्षाओं के कानून तथा पद्धतियों एवम् मानकों का ऐसा उल्लेख किया है ताकि ऐसे कारकों को प्रकाश में लाया जाए जिनकी कोई समीक्षा जांच की जाए ताकि पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति की जांच की जा सके। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ निवेदन किया है कि:

- सामान्य रूप में संबद्ध देशों के निर्यातक और विशेष रूप से आवेदक भारतीय बाजार में इस माल का पाटन अभी भी करते जा रहे हैं।

- घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से होने वाले पाटित आयातों की वजह से क्षति का होना जारी है और यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की पुनरावृत्ति होगी अथवा उसमें और अधिक बढ़ोतरी होगी ।
 - संबद्ध देशों से होने वाले आयातों की निर्यात कीमत तथा लैंडेड कीमत में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद और अधिक गिरावट आई है ।
 - संबद्ध देशों से हुए आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद वृद्धि हुई है ।
 - उत्पादन लागत में वृद्धि होने के बावजूद भारत के लिए निर्यात कीमत में गिरावट आई है ।
 - घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है । जिस कीमत पर घरेलू उद्योग माल की बिक्री कर रहा है वह कोई लाभकारी कीमत नहीं है ।
 - संबद्ध देशों के उत्पादक, विशेष रूप से कोरिया के आवेदक निर्यातक के पास काफी वेशी क्षमताएं मौजूद हैं और संबद्ध देशों में मांग उनकी सृजित क्षमता से काफी कम है । अतः इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप आयातों में प्रवाह बढ़ेगा और घरेलू उद्योग को भारी क्षति होगी ।
 - जर्मनी के उत्पादक मै0 बॉयर एजी ने अपना आधार फ्रांस में स्थानांतरित कर दिया है और अब आयात जर्मनी के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद फ्रांस से हो रहे हैं । चूंकि इस उत्पादक का उत्पादन आधार अनेक देशों में मौजूद है जिनमें उपरोक्त देश शामिल हैं, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि यदि जर्मनी के विरुद्ध यह शुल्क समाप्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जर्मनी से निर्यात पाटित आयातों पर जारी रहेंगे ।
- 102.. प्राधिकारी ने इन तर्कों की जांच आवेदक निर्यातक की क्षमता तथा उत्पादन से संबंधित अपने पास उपलब्ध जानकारी और संबद्ध देशों से हुए आयातों के कीमत स्तर के मद्देनजर की है । यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के विद्यमान रहने के बावजूद संबद्ध देशों से पाटन का होना जारी है हालांकि जर्मनी से हुए आयात की मात्रा बहुत ही कम है ।
103. प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि हालांकि जर्मनी से होने वाले आयात की मात्रा जांच अवधि के दौरान बहुत ही नगण्य रही है लेकिन जर्मनी से होने वाले पाटन की पुनरावृत्ति जर्मनी के मुख्य उत्पादक अर्थात् बॉयर एजी द्वारा अपनी एनबीआर उत्पादन सुविधा फ्रांस में स्थानांतरित किए जाने के तथ्य को देखते हुए जर्मनी से पाटन की पुनरावृत्ति होने की आशंका बनी हुई है । चूंकि यह कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो

यूरोपीय संघ के विभिन्न देशों में अपना प्रचालन कर रही है अतः यह शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में जर्मनी से होने वाले आयात की संभावना से पूर्ण रूप से इंकार नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि बायर एजी, जर्मनी ने इस तर्क का खंडन करने के लिए इस बारे में कोई निवेदन नहीं किया है।

104. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने के बावजूद कोरिया भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहा है और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति जारी है। इसमें वर्ष 2001-02 के दौरान हुई संक्षिप्त वसूली शामिल नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि भारतीय बाजार में पाटित आयात बहुत ही कम कीमत अंतराल पर विभिन्न स्रोतों से साथ-साथ जारी हैं। अतः यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि संबद्ध देशों से होने वाले पाटन के जारी रहने की संभावना है।
105. जहां तक घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने का संबंध है, प्राधिकारी उस कीमत स्तर की ओर ध्यान देता है जिस पर लागू शुल्क के बावजूद संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में माल का आना जारी है। प्राधिकारी नोट करता है कि समीक्षा में शामिल आवेदक सहित विभिन्न देशों के निर्यातकों द्वारा कीमत कटौती अथवा कम कीमत पर काफी बिक्री हो रही है जबकि पाटनरोधी शुल्क बिना मौजूदा आयातों के लैंडेड मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली तथा अक्षतिकारी कीमत से की जाती है। इस बात का कोई संकेत अथवा वैध तर्क नहीं है कि संबद्ध देशों से होने वाले आयातों के कीमत ढांचे में शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में परिवर्तन होगा। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष देता है कि घरेलू उद्योग को यह शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में वास्तविक क्षति का होना जारी रहेगा।

ज. निष्कर्ष:

106. इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा किए गए निवेदनों की जांच के बाद और प्राधिकारी के पास इच्छुक पक्षकारों के निवेदन के जरिए अथवा अन्यथा जैसाकि उपरोक्त जांच परिणामों में उल्लेख किया गया है, के आधार पर और मौजूदा पाटन तथा क्षति की वर्तमान स्थिति और पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष देता है कि:
- संबद्ध माल का भारतीय बाजार में प्रवेश पाटित कीमतों पर हो रहा है और कोरिया गणराज्य तथा जर्मनी से आयातित संबद्ध माल का पाटन मार्जिन काफी है और न्यूनतम से अधिक है;
 - पाटित आयातों के कीमत प्रभाव और बाजार हिस्से में कमी होने की वजह से कम प्रति इकाई वसूली के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को मामूली वास्तविक क्षति होना जारी है;

- iii) संबद्ध देशों से हुए आयातों के संबंध में लगाए गए शुल्क यदि समाप्त किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

झ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

107. पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना होता है जिससे कि भारतीय बाजार में मुक्त तथा उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति कायम हो सके जोकि देश के सामान्य हित में होता है। पाटनरोधी उपायों के किए जाने से संबद्ध देशों के आयातों को किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकेगा। अतः इससे उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट. सिफारिशें

108. इस निष्कर्ष के बाद कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति का होना जारी है और इन शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से हुए आयातों के फलस्वरूप पाटन तथा क्षति के जारी रहने की संभावना है, प्राधिकारी की राय है कि इन देशों से होने वाले आयातों पर उपर्युक्त उपायों को जारी रखना अपेक्षित है। किंतु उपर्युक्त देश से होने वाले पाटन के मौजूदा स्तर और घरेलू उद्योग को हो रही क्षति पर विचार करने के बाद प्राधिकारी की राय है कि लागू उपाय में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अतः, प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है और सिफारिश करता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध माल के हो रहे आयात पर नीचे वर्णित स्वरूप तथा तरीके से पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाए।
109. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कम शुल्क वाले नियम को देखते हुए प्राधिकारी सिफारिश करता है कि पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन, दोनों में से जो भी कम हो, के बराबर की राशि का निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगा दिया जाए जिससे कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति समाप्त की जा सके। इस बात पर विचार करते हुए कि मूल जांच में उल्लिखित शुल्क जिसे सेस्टेट द्वारा संशोधित किया गया था, निर्धारित शुल्क आधार पर लगाया गया था, प्राधिकारी सिफारिश करता है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क में संशोधन किया जाए और उसे जारी रखा जाए, जैसाकि नीचे दी गई सारणी के कॉलम 9 में इंगित किया गया है:-

शुल्क तालिका

क्र	उप-शीर्ष	माल का	विशेष	उद्भव	निर्यात	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क	माप	मुद्रा
-----	----------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	-------	-----	--------

स	अथवा टैरिफ मद	विवरण	विवरण	का देश	का देश			राशि	की इकाई	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4002	एक्रीलो नाइट्राइल बुटाडिन रबड़(एनबी आर)	कोई	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	मै0 कोरिया कुमहो पेट्रोकेमिक ल्स कार्पोरेशन	मै0 कोरिया कुमहो पेट्रोकेमिक ल्स कार्पोरेशन		मी.टन	अम. डा.
2	4002	-वही-	कोई	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई		मी.टन	अम. डा.
3	4002	-वही-	कोई	कोई	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई		मी.टन	अम. डा.
4	4002	-वही-	कोई	कोरिया जन. गण.	कोई	कोई	कोई		मी.टन	अम. डा.
5	4002	-वही-	कोई	जर्मनी	जर्मनी	कोई	कोई		मी.टन	अम. डा.
6	4002	-वही-	कोई	जर्मनी	कोई	कोई	कोई		मी.टन	अम. डा.
7	4002	-वही-	कोई	कोई	जर्मनी	कोई	कोई		मी.टन	अम. डा.

ठ. अगली प्रक्रिया

110. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।
111. प्राधिकारी ऊपर संस्तुत अनुसार निश्चयात्मक उपायों को जारी रखे जाने, उनमें संशोधन करने अथवा उन्हें समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर उपरोक्त अधिनियम के संगत प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार समीक्षा कर सकेगा। प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार की समीक्षा के लिए ऐसे किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी इच्छुक पक्षकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसे दायर नहीं किया गया हो।

क्रिस्टी फर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2005

Mid-Term Review
FINAL FINDINGS

Subject : Mid-term Review of anti-dumping duty imposed on imports of (Acrylonitrile Butadiene Rubber) NBR originating in or exported from Germany and Korea RP.

No. 15/2/2004-DGAD.— WHEREAS, the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (herein after also referred to as the ACT) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after also referred to as Rules), conducted a sunset review of the antidumping duty in force against import of NBR into India from Korea RP and Germany, vide initiation notification dated 1st Oct. 2001 on the basis of an application filed by the M/s Apar Industries Ltd, Mumbai, the domestic producer in India. And Whereas, vide Notification No. 50/1/2001 dated 21st September 2002 the Authority, concluded that the cessation of antidumping duty on NBR from Korea RP and Germany will lead to continuation or recurrence of dumping and injury and recommended continued imposition of definitive antidumping duty on imports of the subject goods. Definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 111/2002-Customs dated 10th October 2002 for a further period of 5 years from the date of this notification. However, in the sunset review the form of duty was changed to reference price basis from the fixed duty imposed in the original investigation. The exporter challenged this shift from fixed to reference price on the landed value basis in the (Customs Excise and service Tax Appellate Tribunal) CESTAT among other issues. CESTAT vide its order No. 14-18/04-AD dated 1/7/2004 modified the form of duty from reference price to fixed duty and the duty amount was fixed as US\$106.16 Per MT against the appellant exporter from Korea i.e. M/s Korea Kumho Petrochemicals Corporation

2. The Designated Authority, received an application on 27th February 2004 from one of the importer in India of the subject goods from Korea RP i.e. M/s Rishirop Polymers Ltd on behalf of a Korean Exporter of the subject goods i.e. M/s Korea Kumho Petrochemicals Corporation for review of the antidumping duties levied on

the subject goods, on the grounds of changed circumstances. On the basis of positive information submitted by the above-mentioned applicant the Designated Authority considered that mid-term review of the Anti Dumping Duty in force would be appropriate in view of the changed circumstances brought to the notice to the authority by the exporter. The Authority issued a public notice dated 29.03.2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping mid term review investigation under Rule 23 of the Antidumping Rules read with Article 11.2 of the Agreement on Antidumping, in respect of the duty in force against the subject countries as above, to determine whether the continued imposition of the duty is required to offset dumping, and whether injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:
 - i) After initiation of the review the Authority sent questionnaires, along-with the initiation notification, to all known exporters/producers in the subject countries, and domestic industry in India in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information;
 - ii) The Embassies/High Commissions/ Representatives of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.
 - iii) Questionnaires were sent to known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).
 - iv) Investigation was carried out for the period starting from 01.01.2003 to 31.12.2003 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2000-01 to 2002-03 and POI.
 - v) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations;
 - vi) No response to the initiation notification was received from any other exporter from the Korea RP except the applicant for this review
 - vii) No other exporter from any of the other countries named, have submitted any response, in any manner, to the initiation notification. M/s Lanxess AG, (Bayer) Germany in its brief submission intimated the Authority that Bayer has internally decided not to invest further resources and expenses arguing its case as it has been reviewed many times by Bayer without any success.

- viii) M/s Apar Industries Ltd. Mumbai, the domestic producer of the subject goods and the original petitioner in the original investigation submitted its responses opposing the review;
- ix) Following other interested parties filed their responses to the initiation notification at various stages of the investigation:
 - a) All India Federation of Rubber Footwear Manufacturers
 - b) All India Rubber Industries Association
- x) The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.
- xi) The Authority made available non-confidential versions of the evidences presented by various interested parties and submissions made by them during the investigation in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xii) The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible to examine the injury suffered and to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicants so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- xiii) The Authority also verified the data of the cooperating exporter and applicant for the subject review, to determine the normal value and dumping margin as per the Rules and prepared a report on the basis of verification carried out in the premises of the exporter. The verification report was made available to the applicant exporter seeking its comments on the same. The exporter however, did not file any comments to the above verification report.
- xiv) The Authority held a public hearing on 15.07.2004 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, exporters of the subject goods from the subject countries. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding;
- xv) The Authority disclosed the essential facts of the case on the basis of which the determinations have been made through separate disclosure statements dated 15th March 2005, to all interested parties. The interested parties were asked to file their comments by 23rd March 2005. The applicant exporter from Korea RP sought an extension of the time for submission of the comments and also sought a hearing before the Authority before the final findings are issued. The exporter was allowed additional time and also two opportunities

or hearing before the Authority. However, the exporter did not avail the opportunity of the hearing granted.

- xvi) Comments to the disclosure statement filed by the interested parties, including the applicant exporter, to the extent they are valid and relevant have been considered in these findings.
- xvii) **** In the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND 'LIKE ARTICLE'

4. The product involved in the said original investigation was Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) falling under heading No. 40025900 in Chapter 40 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS Classification. No argument has been extended, by any interested party, on the issue of product under consideration or like article except the arguments of the applicant exporter that the initiation of the original investigation itself and the product involved in that were disputed by them and the matter is still subjudice. Therefore, the Authority confirms the product under consideration as per the original investigation. This classification is however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

D. Initiation of the Review and arguments raised

D.1 Views of the applicant for the review i.e., M/s Korea Kumho Petrochemical Corporation (KKPC) and M/s Rishiroop Polymers Ltd.

5. The application for the review has been filed by M/s Rishiroop Polymers Ltd. on its own behalf and on behalf of M/s Korea Kumho Petrochemicals Ltd. (KKPC) Korea RP.

6. The applicants in their original application seeking review made the following submissions:

- That market conditions have changed substantially requiring a review of the antidumping measures.
- That the import prices have gone up substantially and the condition of the domestic industry has also improved.
- That there is a significant reduction in the customs duty on the NBR from period of investigation in the earlier review investigation from 38.5% to 20% and therefore, the antidumping duty now collected on reference price basis as a difference between the reference price and the landed value far exceeds the actual dumping margin determined in the sunset review investigation, in violation of Section 9A (1) of the Customs Tariff Act.

7. In summary, the applicant has pleaded that there were sufficient grounds for a changed circumstances review of the antidumping duty in force against them and review initiated is in order.

D.2 Views of the domestic industry:

8. The domestic industry, in its various submissions, has opposed the initiation of the review and has *inter alia* submitted:

- That the present review has been initiated without sufficient justification and based on misleading representation filed by the applicant for the review.
- That the exporter has in fact intensified dumping by absorbing the increase in cost of associated raw materials.
- That quantum of antidumping duty should actually be enhanced to suitably redress the injury to the domestic industry.
- That the applicant exporter failed to provide adequate non-confidential disclosures of its application for review
- That the review should not have been extended to Germany on the basis of a review request made by Korean exporter.

9. In response to the objection of the domestic industry to the initiation of the review the applicants have further submitted that:

- They have requested the authority to initiate a limited and expedient review to revise the reference price so that the anti dumping duty collected did not exceed the dumping margin as the custom duty was revised from 38.5% to 20% during the intervening period. This by itself was adequate evidence constituting changed circumstances necessitating a review. It is an obligation cast on the Authority to undertake mid-term reviews to examine the need for continued imposition of the duty.
- That the domestic industry has been contradicting itself in demanding that a limited review against one country cannot be initiated while an earlier review petition filed by them in 1999 concerning the same matter was withdrawn by them and review terminated by the Authority on the grounds that the Authority could not undertake a limited review against one country when the measure was cumulated against more than one countries and that investigation against all countries was needed to be reviewed simultaneously.
- Against the claim of intensified dumping by the domestic industry the applicant for the review has argued in such a situation the domestic industry should actually support the review rather than opposing it.

D.3 Views of the other interested parties:

10. None of the other interested parties have made any substantial submission in regard to the initiation of the review.

D.4 Examination by the Authority

11. The Authority has carefully examined various submissions made by the interested parties in connection with the initiation of this review investigation.

12. Section 9A (5) read with Rule 23 of the Anti Dumping Rules provides that the Designated Authority shall, from time to time, review the need for continued imposition of anti dumping duty and if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty, shall recommend to the Central Govt. for its withdrawal.

13. Article 11.2 of the Agreement provides that the Authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

14. The domestic industry has argued that under Article 11.2 of ADA read with Rule 23 of Indian Antidumping Rules, substantiation of grounds of review are mandatory and the applicant has failed to do so. Therefore, the initiation of the review is flawed. The applicant exporter has argued that the Indian Law requires the Authority to review the need for continuation of duty from time to time and does not cast an obligation on the party seeking a review to provide substantial evidence. However, they had provided positive information, as required under Article 11.2 of ADA, on several grounds and sufficient information was available with the Authority to initiate a review. They have further argued that substantial reduction in customs duty after imposition of the duty on reference price basis in itself is a sufficient ground to initiate a review as the duty amount collected exceeds the dumping margin violating Section 9A (1) of the Customs Tariff Act and also relevant Articles of the Agreement.

15. The Authority has examined these arguments and is of the view that the condition 'satisfaction' in Rule 23 refers to the satisfaction of the Authority of the need of continued imposition of duty after conducting a proper investigation and not for initiation of the review. What is required for initiating a review is positive information with the Authority on which the Authority can rely upon to decide whether a review is required to examine the need for continued imposition of the duty. In the instant case the applicant had filed sufficient positive information before the Authority in its review application and the review was initiated based on the positive information filed. Production of evidence to substantiate the claims and counter claims by various parties are the matter of investigation and are to be submitted by the parties including the party making a request for review during the course of investigation. The outcome of the review will however, depend upon the quality of evidence submitted by various parties to the review.

16. It has also been argued by the domestic industry that the review should not have been extended to the other country involved i.e. Germany since the request for review was from a single exporter from Korea RP. The Authority is of the view

that the Agreement as well the Rules casts an obligation on the Authority to review the need for continuation of the measures in force. Therefore, nothing in the Agreement or in the Antidumping Rules prevents the Authority from including all countries within the scope of the review when the positive information available with the authority suggests that such a review is appropriate.

17 The Authority has examined all other arguments raised during the investigation and in the post disclosure submissions by the interested parties to the extent they are relevant to the investigation and have analysed them in the findings at appropriate places.

E. DUMPING DETERMINATION

E.1 Republic of Korea

18. Only one exporter/manufacturer from Korea RP i.e. the applicant for the current review, M/s Korea Kumho Petrochemicals Corporation filed its questionnaire response after initiation of the review. The questionnaire response submitted by the exporter was also verified by the Authority as per the procedure prescribed and the dumping margin has been determined as follows:

E.1.1 M/s Korea Kumho Petrochemicals Corporation (KKPC), Korea RP

Normal Value:

19. M/s KKPC filed a detailed questionnaire response with the details of domestic as well as export sales of various grades of NBR produced by its Ulsan Plant. It was observed during the period under consideration the exporter has exported three grades of NBR to India i.e. KNB35, KNB35LM and KNB40M. The exporter also had substantial sale of these grades in its domestic market. Therefore, for the purpose of determination of dumping margin these grades have been accepted as like article within the meaning of the term as per the Agreement.

20. Cost verification of the manufacturer i.e. M/s KKPC, their domestic sales transactions, including various adjustments claimed, were carried out from their records during the on the spot verification. On the basis of the on-the spot verification conducted, a copy of the verification report was sent to the exporter seeking their comments and clarification on various aspects of the verification. However, the exporter did not file any comments even after requesting for additional time for the same. In its post disclosure statement they have argued that the verification report sent to them was without jurisdiction and without any procedure laid down and therefore, not valid. The Authority notes that the verification was duly conducted by competent officers on behalf of the Authority as per the procedure laid down in Annex I to the Agreement and the exporter participated in the said verification. On the basis of verification done and under the authority of the Designated Authority the observations of the verification team, including various elements of the determinations, were communicated to the exporter in the spirit of Article 6(9) of the Agreement. The exporter was also requested to comment on various observations and provide additional information wherever required. The

exporter requested for additional time to comment but failed to file any comment or additional information. Therefore, it was presumed that they did not have anything to comment or oppose in the said report.

21. As far as cost of manufacturing and sales are concerned the Authority notes that the Company incurred substantial expenses towards various R&D expenses in its Rubber manufacturing activities. The exporter has claimed that these expenses are not applicable for the NBR business as the R&D process during the period under investigation covered only specific products. The exporter has reiterated this stand in its post disclosure submissions also. However, the exporter did not file any reply in this respect though this issue was communicated to them through the verification report. The Authority also notes that the exporter has claimed several improvements in NBR productivity in terms of reaction time, consumption norms etc. through their in-house R&D. Therefore, the claim of the Company was not found acceptable as the R&D involved several improvements and developments in the production process covering all products. Accordingly, the R&D cost has been charged to all products on pro-rata basis.

22. Similarly differential adjustment claimed towards packing and transportation claimed for domestic sales and export sales have not been found admissible as no difference was demonstrated between the packing meant for export and domestic sales at the time of verification.

23. Similarly the exporter has not clarified the method of allocation of SGA expenses and factory overheads between various products. The exporter however, did not file any comment to the verification report. Therefore, the issues raised in the verification report were presumed to have been accepted by the exporter. Accordingly, necessary adjustments have been done on these elements of cost to arrive at reasonable cost of production for the exporter. Therefore, cost of production of the subject goods for the exporter has been worked out as US\$ ***** Per MT.

24. KKPC had substantial domestic sales of ***** MT including various grades of NBR during the period under investigation. On the basis of the cost of production so determined, ordinary course of trade test was conducted on their domestic sales transactions. The weighted average of the domestic sale transactions found in the ordinary course of trade has been accepted for determination of their normal value. The exporter has claimed various adjustments to the domestic sale transaction values to arrive at the net ex-factory price. However, the Authority finds that differential adjustments claimed towards inland transportation and packing for the domestic sales and export sales were not adequately substantiated and therefore, the adjustments towards these elements have been admitted on average basis. After applying various admissible level of trade adjustments to the domestic selling price, the ex-factory normal value for this exporter has been determined as US\$ ***** Per MT.

Export Price:

25. During the POI KKPC had exported ***** MT of various grades of NBR to India. Based on the actual CIF price of exports to India net ex-works export price to India has been worked out after adjusting the CIF export price for ocean freight and insurance, inland freight, commission and packing. The claim of the exporter for differential adjustments towards inland transportation and packaging could not be accepted due to lack of sufficient justification and evidence for the same. Based on the above weighted average net ex-works export price has been determined as US\$ ***** Per MT

E.1.2 All other exporters from Korea RP**Normal Value**

26. No other exporter from Korea RP made any submission before the Authority in response to this review investigation. Therefore, for all other exporters from Korea the Authority proposes to determine the normal value on best facts available basis in terms of Rule 6.8 of the Antidumping Rules. For the purpose of this determination highest domestic transaction value of the cooperative exports has been adopted as normal value after allowing admissible adjustments based on cooperative exporter's data. Accordingly the normal value for all other exporters have been determined as US\$***Per MT.

Export Price

27. The net export price has been determined based on the lowest export transaction value from Korea based on the DGCI&S data, after allowing for adjustments towards transportation, ocean freight commission etc. Net export price works out to US\$***per MT.

E.2 Germany

28. The Authority notes that none of the exporters from Germany has responded to the initiation of the review investigation. As noted earlier M/s Lanxess AG, (Bayer) Germany in its brief submission intimated the Authority that Bayer has internally decided not to invest further resources and expenses arguing its case as antidumping duty against this product has been reviewed many times without any success to Bayer. Therefore, the Company has not filed any questionnaire response or cooperated in any manner in the investigation. No other producer/exporter from Germany has filed any response to the investigation. Therefore, the Authority has determined the normal value of the subject goods in Germany on the basis of facts available in terms of Rule 6.8 of the Antidumping Rules. Accordingly, the normal value for all exporters from Germany has been determined as US\$***Per MT

29. The export price from Germany has been determined based on the weighted average export price reported by DGCI&S during the POI after allowing for admissible adjustments towards ocean freight, insurance, inland freight, and

commission on the facts available basis. Accordingly, net ex-works export price for all exporters from Germany has been determined as US\$ ***Per MT.

E.3 Dumping Margin

30. The weighted average normal values determined at the ex-factory level has been compared with the respective weighted average net export prices determined at the ex-factory level to determine the dumping margins for the subject countries as follows:

Dumping Margin Calculations				
	Normal Value US\$/ MT	Export Price US\$/ MT	Dumping Margin US\$/ MT	Dumping Margin %
M/s KKPC, Korea RP	****	****	****	13.22%
All Others exporters from Korea RP	***	***	***	48.75%
All exporters from Germany	***	***	***	93.115

31. The Authority notes that the dumping margin so determined are substantial and above the de minimis levels prescribed.

32. In its post disclosure submissions M/s Rishiroop Polymer, acting on behalf of the applicant exporter, asked for several information, including explanation of the methods of determination of normal value and export prices, as well as adjustments allowed. They also asked for a hearing before the Authority before issue of the final findings and moved a writ petition in the Mumbai High Court in this regard. The Authority accorded several opportunities to them for the said hearing, which they did not avail.

33. M/e Rishiroop in its submissions has argued that the new Designated Authority did not hear the matter before issuing the disclosure. The Authority notes that there is no provision in the Rules for providing a fresh hearing merely because one person is succeeded by another in the post of the Designated Authority. It may be noted that even in quasi-judicial or judicial enquiries the evidence recorded by one quasi-judicial or judicial Authority forms the part and parcel of the material on record and the succeeding person applies his mind on the material on record to arrive at a decision. Rule 6(6) of the Antidumping Rules provide that the oral submissions made by the interested parties before the Authority in the public hearings are necessarily to be reproduced in writing for being taken on record. The written submissions made by the parties after the hearing forms the part and parcel of the records of the investigation on the basis of which the Authority takes the final decision. In the instant case the written submissions made by all interested parties including the applicant, subsequent to the oral hearing held by the earlier Designated Authority, were taken into account by this Authority before issuance of the disclosure statement. However, on the request of the applicant, the Authority extended three opportunities to them to appear before it and make their submissions after the disclosure even though this is not a normal practice of

the Authority. But in spite of their own request for hearing the applicant did not avail these opportunities. Therefore, the Authority does not find any merit in the argument of the applicant in this respect.

34. In their various submissions M/s Rishiroop has raised several issues in respect of power of investigation, power to issue verification report, power of the Authority to conduct the review etc. The Authority notes that the same issues have been raised by them before the Hon'ble Supreme Court earlier and the matter is subjudice without any restraint on the Authority to carry out its investigation as per the Act. The Authority also notes that the investigations are being conducted as per well established practices followed world over and no where the Agreement or the Indian Antidumping Law contemplates that the DA himself will conduct the investigation. Therefore, the arguments of the exporter are not tenable.

35. M/s Rishiroop has also contested the determination of the dumping margin by the Authority. They have argued that the packing cost and inland freight differential between the domestic sales and the export sales as claimed by them have been wrongly disallowed though the same was allowed in the earlier investigations. In this connection the Authority notes that a detailed verification report highlighting the packing and inland freight and R&D expenses issues were sent to the exporter in November 2004. Vide this report several clarifications were also required to be submitted by the party. The exporter, vide its letter dated 19th November asked for time till 30th November to file its response but did not file any comment on the said report till date. Therefore, it was presumed that they did not have anything to comment on the averments made in the said report and the Authority was constrained to proceed on the basis of the facts available with it.

36. The Authority also notes that instead of commenting on the facts brought to their notice much in advance through the verification report, which were in the nature of disclosure of the facts, the exporter has agitated these issues only after the disclosures were issued. However, the Authority has taken note of their objections in their post disclosure comments. It is noted that the difference claimed in the packing cost was disallowed on the basis of actual verification of the production and packing process as well as the data submitted by them and was accordingly, intimated to them in advance. It is further noted that several contradiction have been noticed between their questionnaire response and post disclosure submission regarding the nature of domestic as well as export packing for India. The Authority also notes that in another on-going investigation concerning the same product from other countries no packing difference has been claimed by the exporter, as the packaging is essentially same. Wherever, boxes are used for domestic sales the same is reused for at least 6 to 8 cycles and cost difference becomes negligible.

37. As far as the issue of freight differential is concerned the Authority notes that no inland freight bills in respect of the domestic and export sales were made available for verification with respect to individual invoices. Random invoices produced could not be linked to any specific sale invoices. The whole claim was made on the basis of estimated freight for containerized cargo and road transportation by trucks and the difference appeared to be high in the absence of

actual figures for specific invoices. This aspect was also communicated to the exporter through the verification report. The exporter has not produced further evidence to substantiate its claim. Therefore, the freight element has been worked out on average basis and differential claimed has been disallowed.

38. In view of the above, the Authority is of the view that the dumping margin for them has been determined on the basis of their verified data as intimated to them much in advance and the basis of determination has also been adequately explained to them. Therefore, the Authority does not find any merit in their arguments as far as dumping determination is concerned.

39. In its post disclosure submissions the domestic industry has argued that the dumping margin estimated for the exporter is grossly inadequate as several aspects of their costing has not been taken into account by the Authority in order to arrive at the cost of production in the country of export for the purpose of ordinary course of trade test. They have argued that the costs of principal raw materials have gone up substantially and the exporter seems to have underreported these costs and conversion costs.

40. The Authority notes that the cost of production for the cooperating exporter and the applicant for review in this case was determined by the Authority after verification of their data and after adjusting the same wherever discrepancies were noted. Therefore, the Authority finds no merit in the arguments and confirms the above dumping margin.

F. INJURY DETERMINATION

41. The Rule 23 of the Antidumping Rules provides for review of the need for continued imposition of the antidumping duty from time to time. Such a review requires the Authority to examine whether dumping continues, the degree and extent of such dumping, and injury caused to the domestic industry due to such dumped imports as well as the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury if the duties are removed or modified. Having determined that the imports of the subject goods from the subject countries are entering the Indian market at dumped prices, the Authority examined the injury suffered by the domestic industry and the causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry.

42. The Authority notes that imports of the subject goods are simultaneously entering the Indian market from several countries, including the subject countries for which investigation has been initiated by the Authority. The Authority also notes that imports from several countries have already been treated as dumped imports. Therefore, dumped imports from all such sources have been cumulated for the purpose of examination of the impacts of dumped imports on the domestic industry.

F.1 Continuation of Injury

F.1.1 Views of the interested parties

43. The domestic industry argues that it continues to suffer material injury due

to continued dumping from the subject countries even after imposition of the duties. They have interalia submitted

- That the antidumping duty protection has helped them to improve their performance marginally. But due to intensified dumping by the exporters from the subject countries including the applicant for the review they have not been able to benefit much out of it.
- That In spite of improvement in its productivity and volume of output, reduction in cost of production through various cost cutting measures undertaken, they have failed to realize remunerative prices to recover their cost due to continued dumping from various sources including the subject countries.
- That the applicant exporter has absorbed much of the rise in cost of raw materials and still continues to dump at prices which are unreasonable and thereby causes cash loss to the domestic industry as they are forced to sell below their cost of production in order to retain their market share in the domestic market.

44. The exporters and other interested parties in their various submissions have claimed that performance of the domestic industry has improved and the domestic industry does not suffer material injury. For the sake of brevity various arguments raised by the interested parties in their various written submissions have not been repeated in this finding. However, various submissions have been summarized as follows:

- That Apar's performance has been excellent and that there exists no causal link for any injury caused to them. Their financial results show that they have improved their performance tremendously. All economic indicators are extremely positive for them;
- That Apar's Directors' report annexed to their balance sheets of 1998-99 and 1999-2000 itself reported that they are expanding production capacity to 10000 M ton p.a. Apar would not expand production capacity if it was not operating at high level and are not making adequate profits;
- That world over a production unit of NBR with a capacity of less than 15,000 TPA is considered uneconomical and not viable. Apar's production capacity is said to be 4,000 TPA which is too low a capacity to be cost-effective and profit-worthy;
- That Apar is dependent on others for supply of their raw materials. As the raw material prices are very volatile by nature, they have no control whatsoever, over their production cost and have no option but to subject themselves to vagaries of cost escalation and production losses.
- That there is no shrinkage of Apar's production, sale as well as profit. Their growth rate has been 6% to 7% in line with the growth rate of

rubber industry. Taking requirements of NBR during the next 5 years Apar's capacity would not be able to meet total demand of the industry.

- That their production and sales of Acrylonitrile Butadiene Rubber have gone up significantly. As such, imports of NBR from Korea Republic, Germany or from any other country have no adverse impact on their production, sales and profit. As a matter of fact, their sales and profits continue to rise handsomely.
- That Acrylonitrile and Butadiene Monomer are the basic inputs for the manufacture of NBR. Due to sharp decline in prices of these inputs, there has been downtrend in international prices of NBR over the last four years. Hence, decrease in price of NBR imports from Korea Republic and Germany is no exception.
- That the Indian rubber industry has been put at a disadvantage on account of imposition of anti dumping duty on NBR as their finished products costs are much higher as compared to manufacturers in the neighboring countries.
- That the industry's requirement, both quantity-wise and grade-wise, is far higher than the production capabilities of APAR and as such, the imports are inevitable to meet the demand.
- That Nitrile rubber is produced worldwide in many grades numbering over fifty, which the domestic producer has only 4 to 5 grades to offer to the industry. Therefore, a blanket levy of anti dumping duty on all imported grades is not proper when 90% of the grades are not produced in the country.
- That the petitioners are the sole producers of this product in India. They produce about 4000 M. tons of NBR p.a. whereas the annual consumption is over 10,000 M tons. It defies all logic that even for the quantities that the petitioners have no capacity to produce, the consuming industry is forced to pay anti dumping duty.
- That Apar's annual accounts are in the form of merged balance sheet and it is very difficult to make out clearly about production, sale and profitability of NBR. All businesses of Apar in other areas are going down and substantial growth has been going on in NBR and HSR areas only. The data from first period of investigation till date has been based on their consolidated balance sheet, which contains data on NBR, SBR etc, and they are deliberately doing this to mislead everybody.

45. M/s Rishiroop Polymers in its submissions have argued that the anti dumping measures in India are based on the lesser duty rule and since the dumping margin was found to be lower than the injury margin, the DA applied the measure in the previous period based on the dumping margin thereby leaving a shortfall in the profitability for the domestic industry post the last review. To the extent the gap between the injury margin and the dumping margin determined by the DA in the Sunset review POI, no cause can be attributed for lack of adequate profitability to imports from KKPC and such an impact has not to be attributed to any alleged injury caused by imports from KKPC. They have further argued that there were imports from other sources including those from countries simultaneously being subjected to anti dumping measures and so the impact of imports from those countries at similar or lower landed value needs to be taken into account by the

DA while determining any price effect. There was a reduction in the customs duty in the intervening period between the sunset review and the mid term review POIs and to the extent of the reduction in the landed values of imports from all countries there can be no price effect attributed to KKPC. The conscious act of the Indian Government, to reduce the basic customs duty on the product would have resulted in a price effect on the domestic industry. But that cannot be blamed on the exporter as a ground of lack of adequate profitability to the domestic industry.

46. They have further argued that the DA is incorrectly evaluating the parameter of price undercutting or price suppression and the exporter cannot be held responsible for the landed value of the goods. KPC has control only on the CIF price of the goods that it offers to the Indian importers and any variation in the landed value due to variation in customs duty or exchange rate, etc. is a factor beyond control of KKPC and such factors affecting the evaluation of price undercutting or price suppression during the review POI cannot be attributed to KKPC and must be normalized by the DA when the evaluation of this parameter is made. It is submitted that once this is done the DA will find that there was no cause, since the measures were in force during the review POI far in excess of those required based on reference price level, there was no way that the final landed price could have caused any price undercutting effect on the domestic industry.

47. They have further argued that almost all the economic parameters of the domestic industry are positive, and the main complaint of the domestic industry appears to be lack of adequate profits and it is for the DA to look for the likely reasons for this, which is not due to the imports from KKPC in the review POI.

F.1.2 Views of the Domestic Industry

48. The domestic industry has argued that the claim of the interested parties that there are no losses to Apar industries, and no company, including Apar, can make losses continuously for such a long period, is not correct. They have argued that it is not that the domestic industry has all along made losses or seeking undue protection. The injury information filed by them clearly shows that they have sometime made profits also in respect of this product.

49. They have argued that they have three main business/divisions i.e. Special Oils, NBR/SBR and conductors. Company is performing reasonably well in special oils and conductors. Special oils and conductors business was earlier part of Apart Ltd. and NBR operations were part of Gujarat Apar Polymers Ltd. Company was making continuous losses in NBR business. Continuous losses in NBR business forced the company to merge Apart Ltd. into Gujarat Apar Polymers Limited and pump profits of Special Oils and conductors in NBR-SBR operations. Apart Limited was merged into Gujarat Apart Polymers Limited and name of the Gujarat Apar Polymers Limited was changed to Apar Industries Limited. Therefore, the allegations of projecting artificial losses by the domestic industry or camouflaging their profits are baseless.

F.2 Examination by the Authority

50. The Authority has taken note of various arguments raised by various parties in their submissions and issue of continuation of injury to the domestic industry has been examined in the light of these arguments made before the Authority. The Authority notes that the duty was originally imposed on reference price basis against all exporters from Korea and Germany in the original investigation. The applicant exporter filed an appeal before the Appellate Tribunal against the determinations of the DA and the Appellate Tribunal converted the duty in respect of the appellant into fixed duty basis. It is also noticed that the original request of the applicant in the current review was for a limited review of dumping margin in view of the fact that the duty was on reference price basis and after reduction of the basic customs duty the antidumping duty being collected was exceeding the dumping margin. Therefore, after pronouncement of the new duty structure by the Appellate Tribunal, the basic ground of review by the applicant becomes in fructuous.

51. However, the applicants have challenged the said orders of the Appellate Tribunal in a petition filed in the Hon'ble Supreme Court of India on several grounds and have intimated the Authority that their submissions before the Authority are without prejudice to the outcome of the appeal filed before the Hon'ble Court. Therefore, the Authority notes that since a review has been initiated in terms of Rule 23 of the Antidumping Rules, which requires the Authority to examine the need for continuation of the duty from time to time, this review has been conducted to examine the degree and extent of dumping and injury and the need for continuation of the duty in view of various arguments raised by various interested parties during the investigation.

52. Article 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports the authorities are required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports, the authorities are required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

53. For the purpose of current injury analysis the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its impact on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The arguments of the exporter that the injury to the domestic industry caused by other sources and reduction in basic customs duty has also been addressed by the Authority in its causal links, as well as price undercutting and underselling analysis.

54. Since positive dumping margin has been established for the exports from the subject countries, entire exports from those countries has been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal links examination.

(A) VOLUME EFFECT: Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

55. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined as follows:

i) Import Volumes and share of subject countries:

56. The domestic industry had pleaded that imports of NBR have been reported under various heads of Customs and segregation of NBR is difficult from the DGCI&S transaction-wise data because of the fact that DGCI&S data does not reflect complete description of the product. Therefore, they have relied upon the import data published in the Plastics and Polymer Review (PPR) for the relevant period. The Authority has examined the transaction level data of DGCI&S and also the import data published by PPR for comparison purpose.

57. However, because of the description and classification problem highlighted above the data from these two sources show substantial differences. Moreover, the DGCIS data shows much lower imports from Korea compared to the export data from that country. It is also noted that PPR does not report import through all ports. Therefore, for the purpose of injury analysis the Authority has adopted the DGCI&S data adjusted on the basis of data available with it from other sources. The exporter, in its post disclosure submissions argued that use of such hybrid data for injury analysis is faulty and would benefit the non-cooperating exporters. In this connection the exporter has argued that Para 7 of Annex I to the Agreement and Article 6.8 of the Agreement has not been invoked by the Authority. The Authority notes certain imports have not been accurately captured in the national trade statistics because of misclassification at the time of imports. Therefore, to the extent such misclassified import data was available with the Authority from other sources, they have been used to reasonably estimate the total imports for the purpose of this investigation. At best this estimation is a conservative estimate of the imports of subject goods and does not prejudice the interest of the exporter. Accordingly, the import figures of the product under consideration have been accepted as follows:

Quantity in MT

Particulars	2000-01	2001-02	2002-03	POI
IMPORTS				
Korea	2080	2320	2590	2870
Germany	144	43	36	10
Dumped Imports from Subject Countries	2224	2362	2625	2879
Trend	100	106	118	130
EU, Brazil, Mexico (dumped Imports)	633	847	1709	2094

Others attracting duty (Dumped imports)	356	494	484	553
Dumped imports from all sources	3213	3703	4818	5526
Trend	100	115	150	172
Other un-dumped imports	0	118	217	173
Total	3213	3821	5034	5699
Trend	100	119	157	177

Source: DGC&S

58. The data shows that dumped imports from the subject countries have increased by 30% from the base year in spite of the fact that the imports from these countries are already attracting antidumping duty. Cumulated dumped imports from all sources also show substantial increase of over 70% in the same period. The Authority notes that in a parallel investigation being carried out against the European Union, Brazil, Mexico, and Korea RP for the same product the imports from these countries/territories have been treated as dumped imports. Therefore, for the purpose of the above analysis the imports from these countries have been treated as dumped imports. It is also noted that duty is in force against the imports from Taiwan and Japan. Therefore, dumped imports from all sources have been cumulated for volume analysis.

ii) Demand, Output and Market shares

a) Production of the Domestic Industry

Quantity in MT

Capacity & Production	2000-01	2001-02	2002-03	POI
INSTALLED CAPACITY (NBR)	6,250	8,350	8,800	8,800
Indexed	100	134	141	141
TOTAL PRODUCTION (NBR)	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	130	130	142
GROSS PRODUCTION (NBR BALE ONLY)	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	123	121	130
CAPACITY UTILIZATION % (NBR)	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	97	92	101

59. The production data of the domestic industry reveals that there has been substantial capacity addition in the year 2001-02 and thereafter. However, this addition to the capacity is mainly due to de-bottlenecking of the existing capacity. The domestic industry has also improved its production compared to the base year. The capacity utilization has also improved marginally. However, the capacity addition and production is also to be examined with reference to the growth in demand in the domestic market and the ability of the domestic industry to sell in the domestic market.

60. It is noticed that the demand for NBR in India has shown considerable growth. The domestic industry has submitted that considering sustained positive movement in demand, they had enhanced their capacity by de-bottlenecking the plant capacities incurring an investment of Rs ***** Crores and enhanced the capacity from 6250 MT to 8800 MT. However, they have not been able to increase its production proportionate to increase in capacity as a result of its inability to increase its sales in spite of higher demand. Resultantly, its capacity utilization has not improved and has remained lower than optimum. The domestic industry has claimed that as a result of the adverse NBR operations, the plant has been utilized for production of non-NBR products in order to recover part of the fixed overhead costs.

61. The Authority notes that the increase in capacity of the domestic producer is mostly through de-bottlenecking process and not because of major physical addition to capacity. The increase in capacity was in line with the rise in demand for the product, which is evident from the above data. The production and capacity utilization of the plant also shows a similar trend. But still a part of the capacity has remained unutilized in spite of healthy growth in demand. However, production and capacity utilization when examined along-with the sales of the product during the same period indicates that sales of the domestic producers has not been able to catch up with the demand and production, resulting in inventory built up.

b) Sales of Domestic Industry

		Quantity in MT			
Particulars		2000-01	2001-02	2002-03	Jan 03 - Dec - 03
Opening Stock		*****	*****	*****	*****
Indexed		100	42	145	78
Production		*****	*****	*****	*****
Indexed		100	123	121	130
Domestic sales		*****	*****	*****	*****
Indexed		100	114	118	127
Export sales		*****	*****	*****	*****
Indexed		100	136	138	147
Captive Consumption		*****	*****	*****	*****
Indexed		100	80	98	96
Closing Stock		*****	*****	*****	*****
Indexed		100	341	315	213

62. The data above shows that though the production increased by about 30% compared to the base year and 9% compared to the previous year, the domestic sales has increased by 27% and 9% during the corresponding years. The major increase in the sales is in the export segment though the export volume is low.

b) Demand and Market Share

Quantity in MT

Particulars	2000-01	2001-02	2002-03	Jan 03 – Dec – 03
IMPORTS				
Korea	2080	2320	2590	2870
Germany	144	43	36	10
Imports from Subject Countries	2224	2362	2625	2879
Trend	100	106	118	130
Other Countries Attracting Duty	356	494	484	553
Dumped Imports from Other sources	633	847	1708	2343
Total Others	989	1459	2409	2820
Total Imports	3213	3821	5034	5699
Trend	100	119	157	177
Total Dumped Imports	2857	3209	4333	5222
Domestic sales	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	114	118	127
Captive consumption	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	80	98	96
Demand	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	114	131	144
Share in Demand				
Domestic Industry	54.39%	54.77%	48.97%	48.03%
Dumped Imports from Subject Countries	26.41%	24.70%	23.71%	23.74%
Others (Including dumped imports from other sources)	11.74%	15.26%	21.76%	23.25%
Captive Consumption	7.46%	5.28%	5.56%	4.99%
Share of all dumped imports in Demand	33.92%	33.55%	39.14%	43.05%
Total share of imports in Demand	38.15%	39.95%	45.47%	46.99%

63. Total domestic demand of the product under consideration, has increased by about 44% from the base year but the share of the domestic industry in the total demand has decreased from 54% to 48% during the same period. The share of imports from the subject countries has also declined marginally though there is a substantial increase in absolute term. However, the shares of all imports as well as share of the dumped imports from all sources have increased substantially in spite of the duty in force against the subject countries as well as certain other countries. The data also shows that in spite of increase in production and sales by the domestic industry it has lost substantial market share.

(B) Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

64. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to

the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry (worked out after normating the costing information of the Domestic Industry) have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

(i) Price undercutting and underselling effects

Values in Rs/MT

Price Undercutting and Underselling					
Particulars		2000-01	2001-02	2002-03	Jan 03 Dec -03
Cost of Production	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	82	90	94
Selling Price	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	99	92	96
Landed Value (Subject countries) (without antidumping duty) (Cumulated)	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Landed Value (Cumulated)	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Price undertaking (Subject countries)	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Price under Cutting (Cumulated)	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
% Price undercutting (Subject countries)		0-15%	5-15%	0-15%	5-20%
% Price undercutting (Cumulated)	Rs./MT	0-10%	0-10%	Negative	5-15%
Non Injurious Price	Rs./MT				*****
Price underselling (Subject countries)					*****
Price underselling (Cumulated)	Rs./MT				*****
Price underselling % (Subject Countries)	%				5-20%
Price Underselling % (Cumulated)	%				5-15%

65. The selling price (net sales realization) of the domestic industry shows significant decline though the cost of production after showing a significant decline in 2001-02, has increased substantially. The data also shows that the domestic industry has not been able to raise its prices to remunerative levels to realize its full cost of production.

66. Price undercutting has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from the subject countries over the entire period of investigation with the weighted average net sales realization of the domestic industry for the same period. For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the value reported in the DGCI&S data of import prices from the subject countries.

67. In determining the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been rebated.

78. For the purpose of price underselling determination the weighted average landed price of imports from subject countries has been compared with the Non-injurious selling price of the domestic industry determined for the POI and cost of production for the remaining years.

69. The Authority notes that Imports from the subject countries have been significantly below the net sales realization of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting. The price undercutting and price underselling (without considering the antidumping duty in force) has been found to be substantial. The Authority notes that the subject goods are being simultaneously dumped from certain other countries for which investigations are in progress and the price effect of dumped imports from all sources have been examined cumulatively. The dumped imports from all such sources have been found to have significant price undercutting and underselling effects on the domestic prices.

(ii) Price suppression and depression effects of the dumped imports:

70. The price suppression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values from the subject countries.

71. The cost of production of the subject goods shows substantial increase after showing significant drop in 2001-02. The increase in cost of production is significant due to increase in the cost of raw materials, which constitute major portion of the cost of production. However, the selling price shows decline during the corresponding period indicating the inability of the domestic industry to raise its prices to recover full cost due to price effects of the dumped imports from the subject countries.

72. The Interested parties have argued that the price effect of imports from other dumped sources should also be examined for price undercutting and underselling effects. However, the Authority notes that the imports from all dumped sources have been cumulated for the purpose of injury examination both in terms volume and price effects on the domestic industry as the imports from these sources are like articles entering the Indian market through similar channels during the same period of time and are competing among themselves as well as with the domestic products in the same market. The cumulated imports shows significant price undercutting as well as underselling effect on the domestic prices.

F.3 Examination of other Injury Parameters

73. The Authority has examined the parameters like the actual and potential decline in sales actual and potential decline in capacity and capacity utilization, actual and potential decline in production and market shares etc in the foregoing section which indicated that though there is no decline in sales or production in actual terms the growth in production and sales are much below the potential growth in view of a very healthy growth in demand in the country. The Authority also notes that there is a decline in market shares in spite of good demand and the volume of imports further indicates that there is a further potential for drop in

market share, After examining these parameters the Authority has examined the other mandatory economic factors and indices having bearing on the state of the industry as follows:

i) Actual and potential decline in Productivity

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	Jan 03 - Dec - 03
Productivity	Per Employee	*****	*****	*****	*****
Indexed		100.00	124.18	124.35	138.69
Productivity	MT/Day	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	123.21	120.54	130.22
Productivity per Day - (Considering 360 days of production in a year)					

74. Productivity of the domestic industry has been measured in terms of its labour productivity of the output and daily output and it has been noticed that the productivity has improved substantially. It appears that the industry has attempted to improve its productivity to cut cost and remain competitive. However, improved productivity has not resulted in commensurate profitability because of low realization of its sales.

ii) Profits and actual and potential effects on the cash flow

75. The Authority has taken note of the arguments of the interested parties and the Domestic Industry regarding the financial performance of the Company in its published annual Reports. However, it is also noted that the current investigation is against a specific product manufactured by a multi-product company and the injury examination is to be confined to the domestic operation of the product under consideration and injury if any due to other external factors.

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	Jan - Dec - 03
Cost of Sales	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	85.44	91.05	96
Selling Price	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	98.85	92.47	96
Profit/Loss	Rs. MT	(*****)	****	(*****)	(*****)
Indexed		(100)	19.03	(48.03)	(94.70)
Total Profit/Loss on Domestic Sales	Rs. Lacs	(*****)	*****	(*****)	(*****)
Indexed		(100)	55.46	(84.58)	(113.15)
Depreciation	Rs. Lacs	*****	*****	*****	*****
Indexed		100	100.09	96.49	90.43
Cash Profit/Loss from NBR	Rs. Lacs	(*****)	*****	(*****)	(*****)
Indexed		(100)	325.69	(63.89)	(152.61)

76. The examination of this parameter reveals that though total revenue and cash flow of the domestic industry from its domestic operations of the product under consideration has improved due to increase in domestic production and sales, the industry continues to suffer loss in this product from its domestic operations during the investigation period due to declining per unit realization. The

industry has not been able to realize a fair price to recover its cost due to prevailing price level of dumped imports. The only year in which the domestic industry had a decent profit margin was in the year 2001-02 and thereafter, the financial performance of the company on account of the subject goods have been bad mainly due to low per unit realization.

iii) Actual and potential impact Employment and wages

77. The employment level has declined marginally. But the expenses on account of salary and wages have increased by about 14%. However, increase in the expenses towards salary and wage is in tandem with the increase in production during the comparable periods.

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	Jan - Dec - 03
Employment					
No. of Employee	Nos.	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	104.51	104.51	102.26
Wages		*****	*****	*****	*****
Trend		100	107.94	113.79	116.32
Wage per Employee	Rs. Lacs	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100	103.28	108.88	113.76

iv) Return on investment and ability to raise capital

78. The return on capital employed by the domestic industry shows deterioration compared to the base year and previous years.

Rs in Lacs				
Particulars	2000-01	2001-02	2002-03	Jan - Dec - 03
Capital Employed – (NFA + Working Capital)	*****	*****	*****	*****
Indexed	100.00	96.33	101.84	95.51
Profit	(*****)	*****	(*****)	(*****)
Indexed	(100.00)	55.46	(84.58)	(113.15)
Interest	*****	*****	*****	*****
Indexed	100.00	120.79	106.48	85.35
PBIT	*****	*****	*****	*****
Indexed	100.00	445.27	146.79	34.18
Return on Capital Employed – (NFA + Working Capital)	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	462.23	144.14	35.78

v) Ability to raise capital and investment

79. The Authority notes that domestic industry raised its capacity from 6250 MT to 8800 MT by de-bottlenecking the existing capacity with a capital investment of Rs***** Crore during the period 2001-02, the year in which they had net profit in this product segment. There has been no further fresh investment by the domestic industry during the investigation period and there is no plan for further investment as submitted by them.

1720 GI/05-9

vi) Magnitude of Dumping

80. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry shows that the dumping margin determined against the countries named, for the POI, is substantial, even when the antidumping duty is in force.

vii) Factors affecting domestic prices

81. Change in cost structure if any, competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market. The Authority notes that Landed value of imported material from subject countries is significantly below the selling price of the domestic industry, causing severe price undercutting in the Indian market. The Authority also notes that there is no viable substitute to this product and M/s Apar Industry is the sole producer of the subject good in India and therefore, domestic competition does not affect the prices.

82. The Authority also notes that dumped imports from several sources competing with each other and with the domestic products are simultaneously affecting the domestic market for which cumulative injury analysis has been done. It is also noted that there is a healthy demand of the product in the domestic market.

83. Acrylonitrile and Butadiene are two principal raw materials for production of NBR. Prices of both these monomers increased worldwide. This increase in the prices resulted in increase in the cost of production for the domestic industry over the injury period. However, the selling prices of the domestic industry declined over the injury period.

viii) Inventories

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	Jan - Dec - 03
Inventories - at the end of period	MT	*****	*****	*****	*****
Indexed	%	100	341	315	213
Inventories as % of production		*****%	*****%	*****%	*****%
Trend	Indexed	100	276.85	261.61	163.95

84. The above data indicates a marginal increase in the inventory both in absolute term as well as inventory as a percentage of production.

F.4 Other Known factors and Causal Link

85. The exporter/ importer and other interested parties have argued that factors other than the dumped imports have caused injury to the domestic industry. The exporter has argued that since the antidumping duty is based on lesser duty

principles injury, if any, caused due to change in basic customs duty structure of the country should not be attributed to the dumped imports from the subject countries particularly Korea. They have also argued that since imports are taking place from several countries already attracting duty or under investigation for alleged dumping the effect of these imports should be examined and injury should not be attributed to the imports from Korea.

86. The Authority is of the view that since lesser duty principle is applied by the Authority the duty would be restricted to the extent of dumping only and injury if any caused by reduction of customs duty would not affect the duty level unless the dumping is more than the total injury. As far as causation due to imports from other sources is concerned the Authority has cumulatively examined the volume and price effects of all dumped imports for the purpose of injury analysis as the dumped imports are simultaneously entering the Indian market from several sources, which are under investigation.

87. Though the interested parties have not made any significant argument in respect of other known factors the Authority has examined the non-attribution factors as per the Agreement as follows:

i) Volume and prices of imports from other sources

88. During the POI, other than the subject countries, imports have taken place from several other countries, including Japan and Chinese Taipei against which antidumping duty is in force. The data also shows substantial growth of imports from the European Union (excluding Germany), Brazil and Mexico for which a separate investigation is in progress and preliminary determination of the Authority indicates substantial dumping from these countries. Therefore, imports from all dumped sources have been examined cumulatively to analyse the effect of dumped imports on the domestic industry.

ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

89. Total domestic demand of the product under consideration has shown a very significant increase by about 44% during the period of investigation compared to the base year. There is no significant change in consumption pattern of the product in the domestic market, which can be attributed to the injury to the domestic industry.

iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

90. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. M/s Apar Industries Ltd. is the sole producer of the subject goods in the country. Imports of the subject goods take place from several countries, which compete with the domestic producer. Major portion of the imports from several sources have either been determined as dumped imports or are under investigation for allegation of dumping. Therefore, the Authority notes that the domestic producer is facing unfair competition from several countries

including the subject countries and the current injury to the domestic industry cannot therefore, be attributed to trade restrictive practices or fair competition between foreign and domestic producers.

iv) Development of technology and export performance

91. The production facilities of the cooperating foreign producer in the subject countries were also verified and it was seen that the producers apply similar production technology. In fact most of the producers in the world use the technology developed by technology leaders like Goodyear. Therefore, development of technology or inefficient method of production of the domestic industry cannot be treated as a cause of injury to the domestic industry.

92. The Authority notes that the domestic industry has very small export turnover of the product under consideration though it shows steady growth during the investigation period. Therefore, export performance of the domestic industry is very insignificant and does not affect the domestic industry's performance very significantly.

v) Productivity of the Domestic Industry

93. Productivity of the domestic industry in terms of labour output and daily output has shown substantial improvement. Therefore, productivity is not a factor, which can be attributed to the injury of the domestic industry. In fact domestic industry has tried to reduce its losses in its domestic operation through improvement in productivity.

F.5 Magnitude of Injury and injury margin

94. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports for determination of injury margin. The weighted average landed price of the exports from the subject countries and the injury margins have been found to be significant. In their post disclosure submission the domestic industry has pleaded that the non-injurious price for them has been fixed at a very lower level as several factors including the cost of raw materials, utilities, and reasonable profit margins have not been adequately evaluated. The Authority has taken note of the submissions made on behalf of the domestic industry and is of the view that the NIP has been fixed after a detailed cost verification and normation and therefore, there is no merit in their arguments.

G. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

95. The applicant for the review has argued that since there is no evidence of injurious dumping to the domestic industry in the review POI, the DA is required to examine whether the injury is likely to re-occur should the measures are revoked. The applicant has argued that in order to evaluate this parameter the domestic industry was required to submit concrete tangible evidence regarding the likely volumes of imports from subject countries should the measures be revoked and

the likely prices at which such imports would be made and the likely impact of such imports on their operations so as to cause them to suffer from a re-occurrence of injury in the near future. They have further argued that the anti dumping measure applied during the last 20 months including the review POI based on the variable duty methodology was far in excess of dumping if any and the domestic industry was given a much higher level of protection than required. Therefore, their current injury could not be on account of the said dumped imports.

96. The applicant exporter has further submitted that only claim made by the domestic industry is that there exist sufficient freely disposable capacities with the exporting countries for future likelihood of dumping, which is a general statement without any substantiation and the DA cannot simply rely on it. It is for the domestic industry to produce hard and tangible evidence to stake their claim in this regard. They have further submitted that their production capacity is fully utilized and that it neither has sufficient disposable capacity for export of NBR to India, nor it has any abnormal inventory of the goods to dispose in India. Furthermore, even if there exists such a production capacity in Korea, then also it does not imply that all of this capacity is available for diversion to the Indian market. Thus wild allegations cannot form the basis of any apprehensions for future likelihood of injurious dumping. Concrete evidence should have been produced by the domestic industry to stake their claim in this regard. They have further submitted that there is no anti dumping measure against KKPC for NBR anywhere else in the world such that it would result in KKPC diverting the goods from such country to the Indian market.

97. The interested parties have argued that likelihood test for continuation and recurrence of dumping and injury is not necessary in a review of this nature. They have argued that Section 9A(5) deals with sunset review and not mid term review and Rule 23 nowhere requires likelihood test for dumping and injury in a midterm review. They have submitted that reference to other countries laws is irrelevant, as those pertain to the situation of revocation of anti dumping duty, whereas the present situation is that of continuation of anti dumping duty. In their view the tests and requirements under sunset and midterm review are not the same nor can the same be interchangeably used, given the huge difference in the basic purpose and intent of midterm and sunset review.

98. The domestic industry has submitted that the exporter from Korea continues to dump the material in the Indian market and dumping continues from the subject countries. Further, the capacities of KKPC, other producers in Korea and Germany are much higher than their respective domestic sales/demand. The price difference between the domestic and imported material being huge and the Indian market being highly price sensitive, there is no reason why the imports from the subject countries would not increase, should the present anti dumping duty be withdrawn.

99. The Authority notes the arguments of various interested parties. The Article 11.2 of the ADA provides that

The authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, upon request by any interested party, which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti-dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately

100. Rule 23 of Indian Antidumping Rules requires the Authority to examine the need for continued imposition of the duty from time to time, which also involves an assessment of the likelihood situation of dumping and injury in the event of removal of duty. Therefore, the Authority has examined the current and likelihood aspects of dumping and injury in this matter.

101. Notwithstanding the above the domestic industry has quoted the law and practices and standards of reviews in several countries to highlight the factors that may be examined in a review investigation to examine recurrence of dumping and injury'. They have *inter alia* submitted:

- That the exporters from the subject countries in general, and the applicant for the review in particular, are still dumping the material in the Indian market.
- That Domestic industry is suffering continued injury due to dumped import from subject countries and should the Anti Dumping Duty be revoked, the injury to the domestic industry would recur or intensify.
- That export price and landed price of imports from the subject countries has further declined after imposition of Anti Dumping Duty;
- That Volume of import from subject countries has increased after imposition of antidumping duty.
- In spite of increase in the cost of production the export price to India has declined;
- There is decline in selling price of the domestic industry. The price at which domestic industry is selling material is not a remunerative price.
- That the producers in subject countries, particularly the applicant exporter from Korea are holding significant surplus capacities and the demand in the

subject countries is significantly below the capacities created by them. Therefore, there is a great possibility that revocation of duty would lead to surge in imports and severe injury to the domestic industry.

- That the producer in Germany M/s Bayer AG has shifted its base to France and imports are taking place from France after imposition of antidumping duty against Germany. Since this producer has production base in many countries including the above named countries, the domestic industry has argued that if the duty is revoked against Germany the exports would continue from Germany at dumped prices, even if the import volume from Germany at present is insignificant.

102. The Authority has examined these arguments in the light of the information available with it about the capacity and production of the applicant exporters and the price levels of the imports from the subject countries. It is noted that dumping is continuing from the subject countries in spite of the antidumping duty in force, though volume of imports from Germany is very less.

103. It has been brought to the notice of the Authority that though the volume of imports from Germany is very negligible during the POI the threat of recurrence of dumping from Germany exists in view of the fact the main producer in Germany, i.e. Bayer AG, has shifted its NBR production facility to France. This being a multinational company operating from several countries in the European Union, the possibility of imports from Germany in the event of removal of duty cannot be entirely ruled out. Authority also notes that Bayer AG, Germany has not made any submission in this respect to refute this argument.

104. The Authority also notes that in spite of the antidumping duty being in force the imports from Korea is entering the Indian market at dumped prices and the domestic industry continues to suffer injury except for a brief recovery during 2001-02. It is also noted that dumped imports are entering the Indian market simultaneously from several sources at a very narrow price range competing with each other. Therefore, it can be concluded that the dumping from the subject countries is likely to continue.

105. As far as continuation or recurrence of injury to the domestic industry is concerned the Authority turns to the price levels at which the goods are entering Indian market from the subject countries in spite of the duty in force. The Authority notes that there is a significant price undercutting and underselling by the exporters from the subject countries including the applicant for the review, when the landed value of current imports without antidumping duty is compared with the net sales realization and non-injurious price of the domestic industry. There is no indication or valid argument that the price structure of imports from the subject countries will change once the duty is revoked. Therefore, Authority concludes that the domestic industry would continue to suffer material injury if the duty is revoked.

H. Conclusions

106. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury the authority concludes that:

- i) The subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins of the subject goods imported from Korea RP and Germany are substantial and above de minimis;
- ii) The domestic industry continues to suffer marginal material injury on account of low per unit realization due to the price effect of dumped imports and erosion of its market share;
- iii) Injury to domestic industry is likely to continue or recur if the duties are revoked in respect of imports from the subject countries.

I. Indian industry's interest & other issues

107. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

J. Recommendations

108. Having concluded that the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from the subject countries and there is likelihood of continuation of dumping and injury on account of imports from the subject countries if the duties are revoked, the Authority is of the opinion that continuation of the measure is required against imports from these countries. However, considered the current level of dumping from the subject countries and injury suffered by the domestic industry, the Authority is of the opinion that the measure in force needs to be revised. Therefore, Authority considers it necessary and recommends continuation of anti-dumping duty on imports of subject goods from subject countries in the form and manner described hereunder.

109. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the margin of dumping or margin of injury whichever is lesser, so as to remove the injury to the domestic industry. Considering that the duty in the original investigation as modified by the CESTAT is on fixed duty basis the Authority recommends modification and continuation of definitive antidumping duty on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries, as indicated in Col 9 of the table below.

Duty Table

Sl. No	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	4002	Acrylo Nitrile Butadine Rubber (NBR)	Any	Korea RP	Korea RP	M/s Korea Kumho Petrochemicals Corporation	M/s Korea Kumho Petrochemicals Corporation	138.39	MT	US\$
2	4002	-Do_	Any	Korea RP	Korea RP	Any	Any	362.75	MT	US\$
3	4002	-Do_	Any	Any	Korea RP	Any	Any	362.75	MT	US\$
	4002	-Do_	Any	Korea RP	Any	Any	Any	362.75	MT	US\$
4	4002	-Do_	Any	Germany	Germany	Any	Any	647.35	MT	US\$
5	4002	-Do_	Any	Germany	Any	Any	Any	647.35	MT	US\$
6	4002	-Do_	Any	Any	Germany	Any	Any	647.35	MT	US\$

L. Further Procedures

110. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

111. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the time limit stipulated for this purpose.

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority